IFAD
Investing in rural people

अंक 6, नवम्बर 2015 - जनवरी, 2016

एकीकृत आजीविका संवाद

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

अनुक्रम

स्थायित्व की ओर

हंसा देवी के अभिनव कृषि प्रयोगों के लिए नई उम्मीद एकीकृत आजीविका

02 परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ
03 उत्पादक समूहों की गुणवत्ता
08 आजीविका संगठनों/फैडरेशनों की शीर्ष संस्था-हिलांस
09 आजीविका संगठन गठित
12 टमाटर की खेती से आया समूह में उत्साह
13 उत्पादक समूह संगठित
14 बड़ी इलायची से मिलेगी क्षेत्र को एक अलग पहचान
16 जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति गोसनी द्वारा किये गये विकास कार्य
18 परियोजना के अन्तर्गत रोजगारपरक व्यवसायिक प्रशिक्षण
19 चौलाई उत्पादन बना आजीविका का साधन
20 दीपा की अभिलाषा को मिला परियोजना का सहयोग
21 सफल डेयरी व्यवसाय ने बदली ग्राम की तस्वीर
22 परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित दस्तावेज
23 सहकारिता की आर्थिकी के लिए नया साधन-इन्दिरा अम्मा भोजनालय
24 पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी इलायची की अपार सम्भावनाएँ
26 फैडरेशनों/आजीविका संगठनों का बाजार लिंकेज
27 साहस व हिम्मत की मिसाल बकरी पालन-रतमटिया गाँव

8 नाली बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया

परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS) द्वारा एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के घटक-1 'खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस घटक के अन्तर्गत जनपदों की गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है-

1 आजीविका संगठन

- 85 फैडरेशनों/आजीविका संगठनों द्वारा ₹2414 लाख के टर्नओवर में ₹1520 लाख का लाभ प्राप्त किया गया है।
- 62 नये आजीविका संगठनों का गठन किया जा चुका है।
- 17 नये विकासखण्डों के 1209 ग्रामों में 4621 उत्पादक/निर्बल उत्पादक समूहों का गठन किया जा चुका है, जिनसे 41,482 सदस्य जुड़े हैं। कुल 4,189 उत्पादक समहों के 37,661 सदस्यों को विभिन्न गतिविधियों हेतु ₹1093.29 लाख का वित्तीय सहयोग दिया गया है।

2 विपणन/बाजार पहुँच

- फैडरेशन/आजीविका संगठन, विभिन्न वैल्यूचेन आधारित उत्पादों का विपणन कर रहे हैं। वर्तमान तक 85 फैडरेशन/आजीविका संगठनों द्वारा किये गये विपणन का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वैल्यूचेन	कुल विपणन(₹ में)
1	परम्परागत फसल उत्पादन	₹ 1169.36 लाख
2	बेमौसमी सब्जी उत्पादन	₹ 447.11 लाख
3	उद्यानिकी	₹ 59.55 लाख
4	औषधीय एवं सगंध पौध	₹ 12.74 लाख
5	डेयरी	₹ 160.79 लाख
6	मुर्गीपालन	₹ 36.59 लाख
7	ईकोटूरिज्म	₹ 32.26 लाख
8	गैरकृषि क्षेत्र	₹ 491.02 लाख

- परियोजना द्वारा सहायतित जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं टिहरी की 23 फैडरेशनों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से अपने क्षेत्र में 2300 आंगनबाड़ी केन्द्रों को टेक होम राशन उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। फैडरेशनों द्वारा फरवरी 2014 से जनवरी 2016 तक इस कार्य से ₹715 लाख का व्यवसाय किया गया है।
- वर्तमान तक 02 संग्रहण केन्द्रों (Collection Center) की स्थापना (जनपद अल्मोड़ा) की जा चुकी है। कुल 21 फैडरेशनों के नाम भूमि हस्तांरित हो चुकी है, जिसमें से 4 स्थानों पर संग्रहण केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- जनपद चमोली की फैडरेशनों को 20 कुं. कुटकी की आपूर्ति हेतु कार्याआदेश का अनुबंध इमामी लि. के साथ तथा अन्य जनपदों की फैडरेशनों का 150 कुं. नींबू की आपूर्ति हेतु सेन्टर फॉर टैक्नोलॉजी एंड डॅवलेपमेंट के साथ अनुबंध हो चुका है।
- जनपद अल्मोड़ा के चार फैडरेशनों ने विनोधारा प्रा.लि. को अनुबंध के आधार पर ₹ 1.5 लाख की मटर के बीज की आपूर्ति की है।
- 57 फैडरेशनों ने विपणन हेतु विभिन्न राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के 12 मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करके ₹ 13.05 लाख का बिजनेस/व्यवसाय किया एवं ₹ 12.70 लाख के विपणन ऑर्डर प्राप्त किये।
- परियोजनान्तर्गत बाजार लिंकेज हेतु अभिनव प्रयास करते हुए फैडरेशनों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। चार फैडरेशनों ने 45 कुं. मंडुवा तथा 150 कुं. आलू का बीज एक दूसरे को उपलब्ध कराते हुए इस नवीन पहल की शुरूआत की है।

3 अभिनव कार्यों में पहल

- राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से 13 जनपदों के 325 प्रशिक्षित लाभार्थियों एवं 26 मास्टर ट्रेनरों द्वारा मधुमक्खी गतिविधि प्रारम्भ कर दी गई है। उद्यान विभाग के साथ कन्वर्जेस/अभिसरण करके लाभार्थियों को गतिविधि हेतु बी-कालोनी, बॉक्स एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
- भेड़ एवं ऊन विकास परिषद के समन्वयन से टिहरी, चमोली एवं उत्तरकाशी जनपदों के भेड़पालकों हेतु मशीनों द्वारा भेड़ों की ऊन शियरिंग हेतु कैम्पों का संचालन किया जा रहा है तथा 6 एकीकृत पशुधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- बांस एवं रेशा विकास परिषद के समन्वयन से 6 जनपदों में प्राकृतिक रेशा अधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है तथा प्राकृतिक रेशा आधारित सामुदायिक संसाधन केन्द्र की क्लस्टर स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- कृषि विज्ञान केन्द्र पिथौरागढ़ द्वारा तीन विकासखण्डों के 16 गाँव के 1350 किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली 2.5 लाख प्याज व 2.95 लाख सब्जियों की पौध वितरण का कार्य प्रगति पर। इसके साथ ही 16 गाँव के 900 किसानों को उच्च गुणवत्ता एवं अधिक उत्पादन वाले गिरीदार फलों के पौधे, कीवी, स्ट्रॉबरी एवं बड़ी इलायची के पौधे प्रदान कर मॉडल बगीचों की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

शेष पृष्ठ 17 पर.....

उत्पादक समूहों की गुणवत्ता

विजय कुमार, मुख्य परियोजना निदेशक
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन ईकाई व तकनीकी संस्थाओं ने अथक परिश्रम से एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 8 जनपदों के 16 नये विकासखण्ड के 1211 गाँवों में 44803 परिवारों को शामिल करते हुए 4682 उत्पादक समूहों का गठन किया है। इसके साथ ही हमनें 64 नये आजीविका संगठन का गठन भी किया है। मुझे भलीभांति ज्ञात है कि यह उपलिब्ध बहुत ही सीमित समय में अर्जित की गयी। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

गठित नवीन आजीविका संगठन में से 21 आ. संगठनों के व्यापार आँकड़े आने भी प्रारम्भ हो गये हैं और इन्होंने दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक कुल रु. 15,65,977 का व्यापार कर भी लिया। व्यापार का यह आँकड़ा बहुत उत्साह जनक नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है जिस प्रकार अथक परिश्रम का परिचय देते हुए समूहों व आजीविका संगठन का गठन सीमित समय सीमा के भीतर किया गया उसी प्रकार नव निर्मित समूहों व आजीविका संगठनों में व्यापारिक गतिविधि बढ़ाने की दिशा में प्रभागीय प्रबन्धन ईकाई व तकनीकी संस्थाओं नियोजित तरीके प्रयास प्रारम्भ करेंगी व वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ती तक व्यापार के क्षेत्र प्रभावपूर्ण प्रगति दर्ज करायेंगे।

4682 उत्पादक समूहों का गठन किया जा चुका है। जबकि परियोजना का लक्ष्य 6600 उत्पादक समूहों के गठन का है। अपने लक्ष्य के हम काफी समीप हैं। परियोजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण जनों को आजीविका संवर्धन हेतु उन्हें सक्षम बनाना है। उत्पाद समूहों व आजीविका संगठन का गठन, परियोजना के इस उद्देश्य की दिशा में पहला चरण है। अब हमें उत्पादक समूहों को सशक्त करना है। इस संगठन की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना है। उत्पादक समूहों के साथ कार्य करने की हमारी योजना में निम्न बिन्दु केन्द्र में होने चाहिए :-

- समूह महत्ता व इसकी शक्ति के प्रति जागरूकता।
- गठन के उद्देश्य के प्रति जागरूकता।
- समूहों द्वारा चयन की गयी उत्पादन गतिविधियों के प्रति जागरूकता।

- हमें अब समूहों को उनके द्वारा चयनित उत्पाद गतिविधियों से संबंधित तकनीकी जानकारियाँ नियमित तौर पर पहुँचानी चाहिए। सदस्यों को तकनीकी जानकारियों संबंधी प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों को शीघ्रता से निराकरण भी होना चाहिए।
- समूह को खाद्य सुरक्षा सुधार योजना (FSIP) के संबंध में पूर्ण जानकारी देनी है।
- उत्पाद समूहों के सदस्यों को परियोजना की ओर से मिली सहायता राशि रु. 3600 व उनके द्वारा जमा की अंशराशि रु. 400 के उपयोग का खाद्य सुरक्षा सुधार योजना (FSIP) के अनुसार नियोजन।
- समूहों की नकद व ऋण सीमा (CCL) का मूल्यांकन।
- समूहों को अभिसरण के माध्यम से अन्य ग्रामीण विकास से संबद्ध विभागों की विभिन्न योजनाओं से जोड़ना।
- आजीविका संगठन की महत्ता और इस वृहद संगठन में सदस्यों की सहभागिता किस प्रकार हो सकती है, इस संबंध में जानकारी व ज्ञान का संप्रेषण।
- आजीविका संगठन व उत्पादक समूह के मध्य रिश्तों का सुदृढ़ीकरण।

आशा करता हूँ प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन ईकाई व तकनीकी संस्था बेहतर नियोजन व तय समय सीमा में उत्पादक समूहों को आत्म-निर्भर व सशक्त बनने हेतु प्रेरित करेंगी व परियोजना के लक्ष्य को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान सुनिश्चित करेंगे।

स्थायित्व की ओर

गतिविधि

उत्पादक समूह एवं उनके आजीविका संगठनों/फैडरेशनों द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनुभवों के आदान-प्रदान एवं व्यवसाय हेतु भावी रणनीति बनाने व शीर्ष संगठन विकसित करने हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा दिनांक 08 व 09 दिसम्बर, 2015 को देहरादून में आजीविका संगठनों/फैडरेशनों को राज्य स्तर पर संगठित कर शीर्ष संस्था 'हिलांस' के रूप में गठन करने पर विचार विमर्श करने हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 102 फैडरेशन/आजीविका संगठनों के 222 प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के कार्यक्षेत्र के समस्त आठ जनपदों में कार्यरत कार्यकर्ता व अधिकारीगण, परियोजना के साथ कार्य कर रही तकनीकी संस्थाओं व प्रतिष्ठित कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार श्री प्रीतम सिंह द्वारा दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता डा. आर. बी. एस. रावत, अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा की गयी। श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, सचिव सहकारिता, डा. राकेश शाह, अध्यक्ष, जैव विविधता बोर्ड तथा श्री विजय कुमार, परियोजना निदेशक ने कार्यशाला प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।

कार्यशाला में आजीविका संगठनों के ज्ञानवर्धन व जागरूकता के लिए तैयार किए गए 6 विभिन्न पोस्टरों एवं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का संकलन 'ज्ञान दिग्दर्शिका' व समुदाय आधारित संगठनों की पुस्तिकाओं तथा आजीविका संगठन व उत्पादक समूहों की शीर्ष संस्था 'हिलांस' के नामकरण की पृष्ठभूमि सम्बन्धी 'हिलांस' ब्रोशर का विमोचन माननीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं समस्त अतिथियों द्वारा किया गया।

जैवविविधता बोर्ड के अध्यक्ष ने पहाड़ों मे जैविक खेती तथा कुटकी व पांगर को ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा इसे एक व्यवसाय

के रुप में अपनाने हेतु प्रेरित किया। स्थानीय उत्पादों का G.I. पंजीकरण के बारे में जानकारी प्रदान की।

सचिव सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन ने स्वायत्त सहकारिताओं द्वारा की जा रही व्यवसायिक गतिविधियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारिता विभाग सहकारिताओं को उनकी गुणवत्ता नियंत्रण व उन्हें स्थायी रुप से आगे लाने में मदद करेगा।

मा. मंत्री ग्रामीण विकास ने अपने संबोधन में कहा कि परियोजना को अन्य सभी संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने हेतु शीघ्रता से ठोस योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल देना चाहिए। रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाकर पलायन को रोकने के प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। ग्राम्य विकास से जुड़े समस्त विभागों व परियोजनाओं को मिलकर रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने सहकारिता विभाग के सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि परियोजना जिन फैडरेशनों को वर्ष 2016 में सहयोग देना समाप्त करने जा रही है, उन्हें सहकारिता विभाग से जोड़ना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखण्ड ने परियोजना द्वारा समस्त जनपदों में आजीविका संवर्धन हेतु किये जा रहे बेहतर प्रयासों के लिए प्रसंशा की। उन्होंने कहा कि धनोल्टी में स्थापित किये गये पर्यटन के समुदाय आधारित मॉडल को समस्त जनपदों में लागू किया जाना चाहिए जिससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिल सके। साथ ही उन्होंने जैविक खेती को बढ़ाने, पहाड़ी उत्पादों का उचित भंडारण करने एवं उचित बाजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यशाला में चेतना स्वायत्त सहकारिता अल्मोड़ा, नारी एकता स्वा. सह. अल्मोड़ा, नागटिब्बा स्वा. सह. टिहरी, सप्तऋषि व महासू देवता स्वायत्त सहकारिता उत्तरकाशी के द्वारा अपनी विगत दो वर्षों की प्रगति से सभी को अवगत कराया गया।

विभिन्न प्राईवेट पार्टनर पहाड़ी डाट कॉम, विनोधारा एग्रोटैक, हिमालयन सब्जी भंडार, ईमामी हर्बल कम्पनी, सेंटर फॉर टेक्नालॉजी एवं डेवलपमेंट, के द्वारा अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई।

परियोजना के सलाहकार श्री हरीश चौटानी द्वारा हिलांस संस्था के निर्माण हेतु वैधानिक एक्ट प्रक्रिया व उपयोगिता तथा सुश्री कुसुम रावत द्वारा हिलांस नामकरण की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की गई।

मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक,UGVS ने शीर्ष संस्था के निर्माण हेतु संगठनों के विभिन्न मॉडलों (गैर लाभ वाली संस्थाएं, लाभ वाली संस्थाएं व पारस्परिक लाभ वाली संस्थाएं)पर जानकारी दी, जिससे फैडरेशन/आजीविका संगठन आने वाले समय में व्यापारिक कार्यों से लाभ अर्जित कर सकें।

प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने अपने सम्बोधन में कहा कि परियोजना के सहयोग से राज्य में गठित सहकारिताओं का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। परियोजना द्वारा राज्य स्तर पर एक शीर्ष संस्था के गठन की परिकल्पना एक सराहनीय प्रयास है।

द्वितीय दिवस (9 दिसमबर, 2016)

इस सत्र की अध्यक्षता राज्य के पूर्व मुख्य सचिव श्री एन. रविशंकर द्वारा की गई। दूसरे दिन के प्रथम सत्र का शुभारम्भ करते हुए मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक, UGVS द्वारा शीर्ष संस्था के गठन, कार्यप्रणाली, फैडरेशनों/आजीविका संगठनों के साथ संबंध तथा कानूनी प्रारूप पर प्रतिभागियों को छोटे-छोटे समूहों में चर्चा कराई गई। प्रतिभागियों को चर्चा में प्रभागीय परियोजना प्रबंधकों ने फैसिलिटेट किया। चर्चा के उपरान्त तीनों समूहों द्वारा चर्चा के परिणामों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एन. रविशंकर ने कहा कि हमें सहभागिता व प्रतिभागिता से सहकारिता की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। आजीविका संगठन/फैडेरशनों को हिलांस पर विश्वास होना चाहिए, इसी प्रकार हिलांस को भी अपने सदस्यों पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास और सहभागिता से ही नेतृत्व निकल कर आयेगा। हम लोग मिलकर अपने प्रयासों को स्थायी (sustainable) बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आजीविका संगठन/फैडरेशनों के स्तर पर विपणन को लेकर जो चुनौतियाँ आ रही हैं, उन्हें हिलांस के माध्यम से हल किया जा सकता है। हमें नयी तकनीक की सहायता से एक नयी मार्केटिंग चेन का निर्माण करना चाहिए। हिलांस को मार्केट सर्वे कर बाजार के अनुसार अपने उत्पादों को डिज़ाइन करना चाहिए।

श्रीमती वीरा देवी, अध्यक्ष नंदाकिनी आजीविका स्वायत्त सहकारिता पूर्णकिला, चमोली ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम शीर्ष संस्था के तौर पर तभी सफल हो सकते हैं, जब हम अनुशासन व सुशासन से अपनी सहकारिताओं का संचालन करें। सहकारिताओं के सदस्य के तौर पर हमें अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता है।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में, उत्पाद की मूल्य श्रृंखलाओं की विभिन्न क्रियाओं जैसे- संग्रहण, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा कीमत निर्धारण आदि बिन्दुओं पर श्री राजीव चौधरी द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि उत्पाद के ग्रेड/श्रेणी को चार आधारों पर तय किया जाता है। ग्राहक को सबसे पहले प्रभावित करता है उत्पाद का रंग, जो कि सीधे तौर पर आगतों के स्तर तथा उनकी गुणवत्ता से जुड़ा होता है। दूसरा प्रमुख पैमाना है- उत्पाद का आकार। तीसरी चीज है- उत्पाद अपने आकार के अनुसार सुदृढ़ीकृत है अथवा नहीं। चौथा है-उसका स्वाद। उन्होंने सुझाव दिया कि फसल तोड़ते समय ही उसकी ग्रेडिंग की जानी चाहिए। उत्पाद को कम से कम समय में बाजार पहुँचाया जाए। सामूहिक खेती की अवधारणा से बेहतर उत्पादन किया जा सकता है।

श्री दीपक घनसानी, चार्टेट एकाउन्टेंट द्वारा फैडरेशनों के ऑडिट में आय-व्यय, लेखा संबंधी निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी-

- किसी भी संस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि वित्तीय लेखों को व्यवस्थित रखा जाये। उन्होंने सुझाव दिए कि फैडरेशनों में वित्तीय अनुशासन, स्टॉक रजिस्टरों का उचित
- रखरखाव, समय से बैलेंस शीट तैयार करना तथा कैश बुक प्रविष्टियां करना सुनिश्चित होना चाहिए।
- फैडरेशनों द्वारा किया जा रहा व्यापार उसके लेखों में स्पष्टता से दिखना चाहिए।
- फैडरेशनों में व्यवस्थाओं को विकसित किए जाने की आवश्यकता हैं, जो कि तय करें कि प्रत्येक गतिविधि को कैसे तथा किन-किन चरणों से होते हुए पूरा किया जाए।

परियोजना निदेशक, UGVS ने कहा कि वित्तीय अनुशासन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फैडरेशनों की आर्थिक गतिविधियों का भी सही और सटीक ब्यौरा रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह फैडरेशन को स्थायित्व देने वाले तीन मुख्य स्तम्भों में से एक है। इसी तरह कार्मिक अनुशासन भी इतना ही महत्वपूर्ण है।

कार्यशाला के अन्तिम सत्र की अध्यक्षता डॉ. आर. एस. टोलिया, पूर्व मुख्य सचिव व मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा की गई सत्र की शुरूआत करते हुए परियोजना निदेशक, UGVS ने बताया कि परियोजना के प्रथम चरण में गठित फैडरेशनों की प्रगति को देखते हुए उन्हें वर्तमान में एक रिसोर्स संस्था के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक, UGVS द्वारा प्रस्तावित शीर्ष संस्था-हिलांस को गठित करने का उद्देश्य तथा कार्यशाला में अब तक हुई चर्चाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

प्रतिभगियों ने चर्चा में बताया कि कि आजीविका संगठन डेयरी, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, जड़ी-बूटी एवं फल संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। फैडरेशन प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र के कार्य अनुभवों का आदान-प्रदान किया तथा जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा में परियोजना से सहयोग की मांग की।

परियोजना निदेशक, UGVS ने अवगत कराया गया कि परियोजना फसलों को जंगली जानवरों से होने वाली क्षति से बचाने के लिए 150 गाँवों में पायलट प्रोजक्ट के रूप में समुदाय के साथ मिलकर

मुख्य परियोजना निदेशक ILSP ने कहा कि जिस प्रकार हिलांस पक्षी ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, उसी प्रकार आजीविका संगठनों/फैडेरशनों के व्यापार को हम सभी मिलकर शीर्ष संस्था हिलांस के माध्यम उन्हीं ऊँचायों पर ले जायेंगे। हमें मिट्टी से बाजार (soil to market) की रणनीति पर काम करना होगा। इस रणनीति में हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार उत्पादक समूह व आजीविका संगठन/फैडरेशनों के मध्य संबंधों को और बेहतर बना सकते हैं, इसी प्रकार आजीविका संगठन/फैडरेशनों व हिलांस के मध्य संबंधों पर भी हमें गहनता से विचार करना होगा।

एक ठोस रणनीति के तहत कार्य करने की योजना है। इस हेतु वन्य जीव संस्थान, उत्तराखण्ड एवं पंतनगर विश्वविद्यालय के साथ चर्चा की गई है।

कार्यशाला के सत्र को सम्बोधित करते हुए डॉ.आर.एस. टोलिया ने परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि परियोजना गतिविधियों के माध्यम से समुदाय का क्षमता विकास हुआ है। यह परियोजना की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक, UGVS ने समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दो दिवसीय कार्यशाला का समापन किया।

डॉ. आर.एस. टोलिया ने कहा कि परियोजना ने समुदाय का जो क्षमता विकास किया है उसका लाभ अन्य जगहों पर कैसे मिले इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके द्वारा दिए गये सुझाव निम्नानुसार हैं–

- देहरादून सर्वे चौक स्थित सरस बाजार का उपयोग निकटतम सहकारिताओं द्वारा किया जा सकता है।
- उन्होंने कहा कि यदि हम प्रयास करें तो गाँवों से पलायन कर चुके लोगों को गाँव में वापस ला सकते हैं।
- हमारे क्षेत्र के उत्पादों के लिए मार्केट उपलब्ध नहीं है। हमें अपने उन उत्पादों के बारे में सोचना होगा। इनकी ओर यदि ध्यान न दिया गया तो वे जल्द ही समाप्त हो जायेंगे। इस संबंध में उन्होंने ऊन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में ऊन का उत्पादन बंद होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें ऊन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह चिन्ता का विषय है। सहकारिताओं की शीर्ष संस्था में इस तरह के विषयों पर विचार करना होगा।
- सहकारिताओं से जुड़े लोगों की नियमित आय के बारे में भी सोचना होगा।
- आजीविका संगठन/फैडरेशनों को अन्य सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- आय अर्जित करने के लिए कुछ सहकारिताओं को इंश्योरेंस सेक्टर से भी जोड़ा जा सकता है।
- अपनी योजनाओं में पहाड़ों के मौसम को भी ध्यान में रखना होगा। पहाड़ों में गतिविधियों का संचालन करते हुए हमें उनकी सीमाओं के बारे में सोचना चाहिए। पहाड़ों में उत्पादन की भी सीमा है। इस प्रकार लक्ष्यों को भी इन्हीं सीमाओं में रख कर विचार करना चाहिए।
- पहाड़ के स्थानीय मेलों से स्थानीय उत्पाद गायब हैं। उन्होंने प्रदेश व देश में आयोजित विभिन्न मेलों/प्रदर्शनियों में सहकारितायों की अधिक भागीदरी पर भी बल दिया।
- उन्होनें सुझाया कि जो फैडरेशन अच्छा कार्य कर रही हैं, उन्हें प्रोत्साहन देकर उत्साहित करने की आवश्यकता है।

गतिविधि

आजीविका संगठनों/फैडरेशनों की शीर्ष संस्था –'हिलांस'

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा देहरादून में उत्पादक समूहों एवं आजीविका संगठनों/फैडरेशनों की व्यावसायिक गतिविधयों को राज्य स्तर से सहयोग हेतु शीर्ष संस्था 'हिलांस' के गठन के लिए फैडरेशन/आजीविका संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श हेतु दिनांक 08–09 दिसम्बर, 2015 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शीर्ष संस्था की आवश्यकता एवं गठन पर छोटे–छोटे समूहों में गहन चर्चा की गई। कार्यशाला में उपस्थित समूह प्रतिनिधयों द्वारा इस चर्चा के परिणामों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

तीनों समूहों ने मंच पर अपने प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि फैडरेशनों के सुखद भविष्य के लिए शीर्ष संस्था हिलांस की बहुत आवश्यकता है। इससे एक ओर जहाँ फैडरेशनों को राज्य स्तर व्यापार का एक मंच मिलेगा, वहीं उन्हें अपने विभिन्न उत्पादों की बाजार की आवश्यकता के अनुरूप पैकेजिंग, ग्रेडिंग करने हेतु सहयोग प्राप्त होगा। आजीविका संगठन के माध्यम से उत्पादित किये जा रहे उत्पादों को एक राष्ट्रीय स्तर का ब्राण्ड मिलेगा जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।

समूहों के प्रस्तुतीकरण में आये मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

आजीविका संगठनों/फैडरेशनों को शीर्ष संस्था –'हिलांस' की आवश्यकता क्यों है ?

तीनों समूहों ने हिलांस की आवश्यकता को निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक समझा–

- शीर्ष संस्था द्वारा सहकारिताओं द्वारा उत्पादित किये जा रहे उत्पादों की मार्केटिंग हेतु।
- समूह एवं सहकारितायें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ सकें जिससे ग्राम स्तरीय व्यापार में बढ़ोतरी हो सके।
- उत्पादों व सेवाओं के बेहतर मूल्य निर्धारण हेतु।
- आजीविका संगठनों/फैडरेशनों के मार्गदर्शन तथा उच्च स्तरीय सहयोग के लिए।
- आवश्यकता पड़ने पर बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए।
- बेहतर कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए।
- प्रशिक्षणों के माध्यम से आजीविका संगठनों/फैडरेशनों की क्षमता विकास व नेतृत्व विकास के लिए।

- उत्पादन व विपणन हेतु आवश्यक ज्ञान तथा बेहतर तकनीकी उपलब्ध करवाने के लिए।
- उत्पाद मूल्य संवर्धन के लिए।
- सहकारिताओं के उत्पादों की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ब्राडिंग तथा पहचान के लिए।
- आगतों की आपूर्ति, आवश्यक व आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए।
- आजीविका संगठनों/फैडरेशनों के उत्पादों के ई. कामर्स के माध्यम से बेहतर विपणन के लिए।

• शीर्ष संस्था में वर्तमान आजीविका संगठनों/फैडरेशनों की भागीदारी किस प्रकार की होगी?

- शेयर पूंजी के माध्यम से।
- व्यावसायिक सहभागिता–सेवा शुल्क के माध्यम से
- शीर्ष संस्था के नेतृत्वकारी निकाय में फैडरेशनों के सीधे प्रतिनिधित्व के माध्यम से।

प्रस्तावित शीर्ष संस्था के पंजीकरण का कानूनी प्रारूप क्या होगा ?

- एक समूह ने उत्पादक कम्पनी, एक समूह ने स्वायत्त सहकारिता के विकल्प का सुझाव दिया तथा एक समूह ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की।
- सभी समूहों ने कहा उनके लिए कोई भी वह विकल्प सही होगा जो उन्हें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करायेगा।

श्री मनोज रावत
कार्यक्रम प्रबंधक: मार्केट एक्सेस
UGVS-ILSP

62 आजीविका संगठन गठित

60 आजीविका संगठनों का पंजीकरण सम्पन्न

गतिविधि

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत आजीविका संवर्द्धन की प्रक्रिया के दूसरे चरण में उत्पादक समूहों के द्वितीय स्तर के संगठन 'आजीविका संगठनों (LC) का गठन किया जा रहा है। वर्तमान तक कुल 62 आजीविका संगठनों का गठन किया जा चुका है तथा गठित आजीविका संगठनों में से कुल 60 पंजीकृत हो चुके हैं। इस त्रैमास में पंजीकृत आजीविका संगठनों का जनपदवार विवरण इस प्रकार से है-

जनपद पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ के मुनाकोट विकासखण्ड में **मनमहेश आजीविका तथा त्रिपुरा सुंदरी** स्वायत्त सहकारिताओं को पंजीकृत कराया जा चुका है, जिनका विकासखण्डवार विवरण निम्नानुसार है-

आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
मनमहेश आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती अंजू भट्ट	मजरीकांडा
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती कमला मेहरा	गौराहाट
	सचिव- श्रीमती लक्ष्मी देवी	गौराहाट
त्रिपुरा सुंदरी आजीविका स्वा.	अध्यक्ष- श्रीमती जानकी कपरै	झूलाघाट
	कोषाध्यक्ष- श्री दीप चंद	कनरी
	सचिव- श्रीमती हेमलता ओली	झूलाघाट

जनपद टिहरी

जनपद टिहरी में इस त्रैमास में कुल 6 आजीविका संगठनों को पंजीकृत कराया जा चुका है। पंजीकृत आजीविका संगठनों के प्रतिनिधियों का विकासखण्डवार विवरण निम्नवत् है-

विकासखण्ड-जौनपुर		
आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
दसजुला स्वायत्त सहकारिता	अध्यक्ष- श्रीमती सरिता देवी	गौरन
	कोषाध्यक्ष- श्री गजेंद्र सिंह	किमोरा
	सचिव- श्रीमती शीला देवी	कंडलगांव
देवभूमि स्वायत्त सहकारिता	अध्यक्ष- श्रीमती संगीता देवी	भनेसरी
	कोषाध्यक्ष- श्री रमेश प्रसाद	थान
	सचिव- श्रीमती सरोजनी देवी	गड़ेथगांव

विकासखण्ड-चम्बा		
आजीविका	संगठन	निदेशक
बेलमती स्वायत्त सहकारिता	अध्यक्ष- श्रीमती बीना देवी	घरगाँव
	सचिव- श्रीमती शशी देवी	कठूड
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती पूजा देवी	करत्वाल
सुरसिंग देवता एकी. आजी.	अध्यक्ष- श्रीमती ममता बेलवाल	कंडाखोली
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती मंजू देवी	ग्वार्द
	सचिव- श्रीमती यशोदा देवी	कांडा
चम्बा मसूरी बागवानी एकीकृत आजीविका स्वा. सह.		
उत्साह स्वायत्त सहकारिता		

जनपद उत्तरकाशी

जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखण्ड में दो आजीविका संगठन का गठन कर पंजीकरण कर लिया गया है जिनके प्रतिनिधियों का विवरण निम्नवत् है-

आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
हरि महाराज आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती सरोजनी भट्ट	मनपुर
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती श्याम कुमारी	सरा
	सचिव- श्रीमती अनिता गुसाईं	बोंगरी
माँ जगदम्बा अजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती देवेंद्री देवी	बरसू
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती कविता देवी	बंदरानी
	सचिव- श्रीमती सुनीता देवी	भटवाड़ी

जनपद अल्मोड़ा

जनपद अल्मोड़ा में इस त्रैमास में कुल 8 आजीविका संगठनों को पंजीकृत कराया जा चुका है। पंजीकृत आजीविका संगठनों के प्रतिनिधियों का विकासखण्डवार विवरण निम्नवत् है–

विकासखण्ड–चौखुटिया		
आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
जय भूमियाल बाबा स्वायत्त सहकारिता	अध्यक्ष– श्रीमती कौशल्या देवी	भगोती
	कोषाध्यक्ष– श्रीमती हेमलता देवी	भटकोट
	सचिव– श्रीमती मोहनी देवी	भगोती
रामगंगा स्वायत्त सहकारिता	अध्यक्ष– श्रीमती भावना देवी	फुलई
	कोषाध्यक्ष– श्रीमती पुष्पा देवी	–
	सचिव– श्रीमती भवानी देवी	टेडागाँव
ताल ग्वाड घाटी स्वायत्त सहकारिता	अध्यक्ष– श्रीमती उर्मिला देवी	मोहना
	कोषाध्यक्ष– श्रीमती दीपा देवी	–
	सचिव– श्रीमती मीनाक्षी देवी	आदिग्राम

विकासखण्ड–भिकियासैंण		
आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
महाकालेश्वर आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष– श्रीमती माया देवी	दधौली
	कोषाध्यक्ष– श्रीमती कल्पना देवी	पिपलिया
	सचिव– श्रीमती मोहनी देवी	चनोली

विकासखण्ड–हवालबाग		
आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
प्रगति आजीविका स्वा. सहकारिता	अध्यक्ष– श्री सुरेन्द्र सिंह	बेह
	कोषाध्यक्ष– श्रीमती दीपा मेहता	मेहतागांव
	सचिव– श्रीमती मंजू देवी	कनालबूंगा
शीतला स्वायत्त सहकारिता	अध्यक्ष– श्रीमती निर्मला तिवारी	पिपोलीखान
	कोषाध्यक्ष– श्रीमती नीतू देवी	कुरछोन
	सचिव– श्री भुवन भट्ट	बदलगलभट

जनपद बागेश्वर

जनपद बागेश्वर में इस त्रैमास में गरूड़ विकासखण्ड में तीन आजीविका संगठनों– अन्नपूर्ण आजीविका स्वायत्त सहकारिता, हिमगिरि आजीविका स्वायत्त सहकारिता, लहुर अजीविका स्वायत्त सहकारिता तथा संजीवनी आजीविका स्वायत्त सहकारिता का गठन करके पंजीकृत किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
अन्नपूर्णा आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष– श्रीमती लता किरोला	स्याली
	सचिव– श्रीमती जानकी देवी	हरिनगरी
	कोषाध्यक्ष– श्रीमती रमा देवी	–
हिमगिरि आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष– श्रीमती चम्पा देवी	रतौडा
	कोषाध्यक्ष– श्रीमती ममता देवी	रतमटिया
	सचिव– श्रीमती मुन्नी पाण्डे	कौसानी
लहुर आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष– श्रीमती जानकी परिहर	तिलसारी
	कोषाध्यक्ष– श्रीमती प्रेमा मिश्रा	बैंगांव
	सचिव– श्री किशनलाल	जखेडा
संजीवनी आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष– श्रीमती हेमलता देवी	नौघर
	कोषाध्यक्ष– श्रीमती खष्टी देवी	ढैना
	सचिव– श्री काम सिंह	

जनपद चमोली

जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली में इस त्रैमास में **बंधनगढ़ी आजीविका स्वायत्त सहकारिता** का गठन कर पंजीकरण कर लिया गया है, जिसके निदेशक मंडल के प्रतिनिधियों का विवरण इस प्रकार से है–

निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
अध्यक्ष– श्रीमती सुषमा खम्पा	ग्वालदम
कोषाध्यक्ष– श्रीमती संतोषी देवी	त्रिकोट
सचिव– श्रीमती कल्पेश्वरी देवी	ताल

हंसा देवी के अभिनव कृषि प्रयोगों के लिए नई उम्मीद एकीकृत आजीविका

सफल प्रयोग

चम्बा, टिहरी

खड़ीखाल गाँव, चंबा विकासखंड के डडूर न्याय पंचायत में आता है। गाँव में तकरीबन 95 परिवार रहते हैं। यहाँ जीवनयापन हेतु मुख्य पेशा कृषि एवं पशुपालन हैं। इसके अलावा मजदूरी करके भी लोग आजीविका चलाते हैं। कई परिवार बेहतर रोजगार एवं शिक्षा के लिए यहां से पलायन भी कर चुके हैं। किसान परम्परागत कृषि के अतिरिक्त सब्जियों की खेती भी करते हैं। पत्तागोभी एवं आलू की खेती यहाँ बहुतायत में होती है।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा तकनीकी संस्था ए. टी.आई. के माध्यम से गाँव में गठित उत्पादक समूहों को उत्पादन एवं विपणन की जानकारी दी जाती है। तकनीकी संस्था द्वारा गाँव में एक खुली बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम प्रधान, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं किसानों ने प्रतिभाग किया। तकनीकी संस्था एवं प्रभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रतिनिधियों ने उत्पादक समूहों के माध्यम से होने वाले लाभ जैसे उत्पादन व विपणन में होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। साथ ही समूह के सदस्य बनने की पात्रता एवं समूहों के उच्च स्तरीय संगठन आजीविका संगठन की प्रक्रिया पर चर्चा की। किसानों को जैसे-जैसे परियोजना के उद्देश्य व प्राथमिकताएं स्पष्ट होती गई, वैसे-वैसे वह परियोजना से जुड़ते गए। किसानों का समूह बनाकर उत्पादन करना गाँव वालों के लिए नई पहल थी।

कुंजापुरी उत्पादक समूह, खड़ीखाल गाँव का प्रथम उत्पादक समूह है। पत्तागोभी उत्पादन, इस समूह की पहली गतिविधि है। श्रीमती हंसा देवी इस समूह की सदस्य हैं। वह सामान्य परिवार से हैं। परिवार में पति सतेन्द्र सिंह पुण्डीर के अलावा तीन पुत्र हैं। हंसा देवी एवं उनके पति कृषि कार्यों के साथ ही गाँव की अन्य गतिविधियों में मजदूरी भी करते हैं। हंसा देवी एक प्रगतिशील किसान हैं। उनकी विशेषता है कि वह अपने कृषि कार्यों में अन्वेषण एवं नये प्रयोग भी करती हैं। परिवार के लोग बताते हैं, कि परियोजना से जुड़ने के बाद हंसा देवी के व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आया है। उनके इस आत्मविश्वास का आधार है परियोजना का आर्थिक और तकनीकी सहयोग एवं बेहतर भविष्य की वह उम्मीद जो परियोजना से जुड़ कर उन्हें मिली है।

आम तौर पर पत्तागोभी की एक पौध में एक बंद लगता है, परंतु हंसा देवी ने अपने अन्वेषण व प्रयोग से गोभी के पौधे को पेड़ बना दिया है। उनके घर पर लगे हुए पत्तागोभी के एक पेड़ में 30 से 40 बंद तक लगते हैं। वह पत्तागोभी का बीज भी बनाती हैं। वह कहती हैं कि परियोजना से उनके इस अन्वेषण को आर्थिक ही नहीं बल्कि तकनीकी सहयोग भी प्राप्त हुआ है।

कृषक द्वारा तैयार पत्ता गोभी का पेड़

इस समय उनकी प्रायोगिक क्यारी में लगी हुई पत्तागोभी के पेड़ पर तकरीबन 30-40 बंद बन चुके हैं। हंसा देवी बताती हैं कि इस तरह पत्तागोभी के पेड़ पर लगने वाले गोभी के बंद हालांकि छोटे होते हैं परंतु जितनी ज्यादा मात्रा में यह लगते हैं उससे उत्पादन तीन गुना तक बढ़ सकता है।

हंसा देवी को भरोसा है कि परियोजना से मिल रहा तकनीकी सहयोग उनके साथ आगे भी जारी रहेगा। पत्तागोभी की इस प्रयोगात्मक खेती को और भी ज्यादा व्यावहारिक तथा ज्यादा परिणामोत्पादक बनाने के लिए उन्हें सहायता मिलेगी। हंसा देवी अपने पत्तागोभी के पेड़ों के माध्यम से अगली फसल के लिए बीज भी बनाना चाहती हैं। हंसा देवी व उसका परिवार, गाँव वालों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। जब भी फसल में कोई समस्या होती है तो अन्य महिलाएं इनकी एवं इनसे सलाह जरूर लेती है।

प्रभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई, टिहरी

UGVS-ILSP

गतिविधि

टमाटर की खेती से आया समूह में उत्साह

गरूड़, बागेश्वर

बागेश्वर जनपद के गरूड़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत रतोड़ा के अन्तर्गत बांज और चीड़ के जंगल से घिरा एक छोटा सा तोक है मझारचौंरा। इस तोक में कुल 6 परिवार निवास करते हैं। सभी परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले हैं। ये परिवार अब नयी तकनीक से कृषि करने एवं पशुपालन से क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की तकनीकी संस्था श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के कार्यकर्ताओं ने परियोजना के प्रारम्भिक दौर में क्षेत्र के भ्रमण के दौरान देखा कि मझारचौंरा तोक पर सभी परिवारों की कृषि भूमि एक ही जगह पर है। यहाँ पर समूह के माध्यम से सभी परिवार मिलकर अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ रह रहे परिवारों के साथ परियोजना की गतिविधियों पर चर्चा प्रारम्भ की गयी। गाँव वालों ने बताया कि वे सब्जी उत्पादन द्वारा ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। स्थानीय बाजार गरूड़ एवं कौसानी जाकर वे अपनी सब्जियों का विपणन करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा उन्हें बीज उत्पादन एवं पॉलीहाउस हेतु सहयोग भी प्राप्त हुआ है।

संगठनात्मक रूप से आजीविका सुधार हेतु कार्य करने के उद्देश्य से तोक के सभी 6 परिवारों ने मिलकर 'न्यू ज्योति उत्पादक समूह' का गठन किया। टमाटर पौध नर्सरी एवं टमाटर उत्पादन गतिविधियों को समूह की प्राथमिक गतिविधियों के रूप में चुना गया। बैंक में खाता खुलवाने पर परियोजना द्वारा गतिविधि सहयोग राशि समूह को प्रदान की गयी। समूह के अध्यक्ष श्री भूपाल सिंह जी के नेतृत्व में जून 2015 में टमाटर का उन्नत किस्म का बीज क्रय कर सभी सदस्यों में वितरित किया गया। इन बीजों के माध्यम से सदस्यों ने मिलकर टमाटर की पौधशाला तैयार की। 3 से 5 नाली (कुल 22 नाली) में टमाटर पौध का रोपण किया गया। शेष बची लगभग दस हजार पौध को आसपास के 15 गाँवों के किसानों को बेचा गया। समूह ने पौध विपणन से कुल ₹10,000.00 की आय अर्जित की। किसानों ने अपने खेतों में कुल 04 कुन्तल टमाटर का उत्पादन किया। इस टमाटर को स्थानीय बाजार गरूड़ एवं कौसानी में विपणन करने से समूह को ₹ 15,000.00 हजार का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार समूह ने अपनी गतिविधि के माध्यम से कुल ₹ 25,000.00 की आय अर्जित की। इसके अतिरिक्त समूह द्वारा अन्य सब्जियों जैसे गोभी, मटर, राई, बैंगन व गडेरी का उत्पादन भी किया गया है। इनके विपणन से समूह ने कुल ₹47,000.00 की आय प्राप्त की। इस प्रकार अपने उत्पाद के माध्यम से समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा लगभग ₹ 12,000.00 की आय प्राप्त की गई।

टमाटर पौध उत्पादन एवं अन्य सब्जी उत्पादन करने के दौरान कुछ पौध गलने से नुकसान भी हुआ। आपस में चर्चा कर इन समस्याओं का समाधान भी निकाला गया। पौध गलने से जिस स्थान पर नुकसान हुआ है वहां पर राई लगायी गयी। इससे एक साथ दो फसले तैयार हो जायेगी।

समूह अध्यक्ष श्री भूपाल सिह हिमगिरि आजीविका संगठन के प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य भी हैं। उन्होंने 'व्यापार कार्य योजना कार्यशाला' के दौरान अपने अनुभवों को बांटते हुए कहा कि कृषि उत्पादन को हमें व्यवसाय मान कर नयी तकनीक के साथ कृषि करनी चाहिए। इस प्रकार हमें निश्चित रूप्से अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। बन्दर और अन्य जंगली जानवरों का खतरा तो हमेशा बना रहता है। हमें इन सभी चुनौतियों का सामना करने की रणनीति बनानी चाहिए। परियोजना के माध्यम से मिल रहे तकनीकी ज्ञान का हमें उपयोग करना चाहिए। उससे हमारा उत्पादन तो बढ़ेगा ही साथ ही विपणन के नये विकल्प भी निर्मित होंगे।

प्रभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई, बागेश्वर

UGVS-ILSP

उत्पादक समूह संगठित

प्रेरणा

जखोली, रूद्रप्रयाग

मैं तकनीकी संस्था असीड की ओर से जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के 4 गाँवों में आजीविका सुगमकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ।

जब मैंने गाँव में काम करना शुरू किया तो महिलाओं को एक समूह में एकत्रित करना बहुत मुश्किल होता था। किसी को परियोजना पर विश्वास नहीं होता था। कई बार समूह गठन हुआ लेकिन अंतिम समय पर पदाधिकारी चयन के समय उत्पन्न मतभेद के कारण समूह टूटे। कुछ समूह बैंक खाता खुलवाने भी नहीं आये।

निरन्तर सम्पर्क व चर्चा से स्थिति में बदलाव आया और अब गाँव की अधिकरतर महिलाएँ परियोजना से जुड़ चुकीं हैं। उन्होंने अपने-अपने उत्पादक समूह बना लिए हैं। वर्तमान में मेरे कार्यक्षेत्र में 20 उत्पादक व निर्बल उत्पादक समूहों के माध्यम से 155 परिवार परियोजना से जुड़ चुके हैं। एकीकृत परियोजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी उत्पादक समूह अपने दस्तावेजों का स्वयं रखरखाव कर रहे हैं। आय-व्यय रजिस्टर भरना सीखने के बाद महिलायें स्वयं अपने रजिस्टर भर रही हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास जगा है। अपने इसी आत्मविश्वास के कारण उन्होंने अपनी कृषि को वैज्ञानिक ढंग से करने की इच्छा व्यक्त की है। वे अक्सर इस संबंध में प्रश्न करती हैं। वे उन्नत खेती की दिशा में प्रयास करना चाहती है।

मैं अपने टेबलेट के माध्यम से समूह की महिलाओं को परियोजना की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाती हूँ। इससे महिलाऐं काफी उत्साहित होती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है।

परियोजना से किसान महिलाओं को ही नहीं हम कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है जैसे समूह व महिला/पुरूषों से कैसे बातचीत करनी है, समूह में एकता बनाये रखने के लिए क्या करना व क्या सिखाना है, समूह व ग्राम स्तर पर उत्पन्न मतभेदों का निराकरण इत्यादि।

परियोजना किसानों व क्षेत्र के लिए अवश्य वरदान साबित होगी व हम कार्यकर्ता परियोजना के सफलता क्रियान्वयन में पूरी मेहनत एवं सहयोग करेंगे। धन्यवाद।

मोनिका थपलियाल
आजीविका सुगमकर्ता, असीड
जखोली, रूद्रप्रयाग, UGVS-ILSP

पशुपालन विभाग, टिहरी द्वारा परियोजना क्षेत्र के जौनपुर, चम्बा एवं फकोट क्षेत्र में पशुचारा विकास हेतु उत्पादक समूहों के 650 सदस्यों के साथ 3885 चारा प्रजाति एवं 133.7 कुं. नैपियर का रोपण।

बड़ी इलायची से मिलेगी क्षेत्र को एक अलग पहचान

गतिविधि

जखोली, रूद्रप्रयाग

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकासखण्ड जखोली व अगस्तमुनि में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यतः कृषि आधारित व्यवसाय के माध्यम से आजीविका सुधार के इस कार्यक्रम में रूद्रप्रयाग जनपद में जो मुख्य चुनौती सामने आयी, वह थी- जंगली जानवरों जैसे-बन्दर, सुअर तथा कुरमुला द्वारा फसलों को नष्ट करना। कुछ गाँवों में तो स्थिति इतनी खराब थी कि लगभग 60% फसल को जंगली जानवरों व कीटों द्वारा नुकसान पहुँचाया गया था। वहीं हरीपुर लौंगा गाँव, विकासखण्ड जखोली के कृषकों ने बड़ी इलायची उत्पादन का निर्णय कर इस समस्या का हल निकाला।

बड़ी इलायची की फसल को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान नहीं पहुँचाया जाता व फसल पर बहुत कम बीमारियों व कीटों का प्रकोप होता है। बड़ी इलायची कम लागत में अच्छी आमदनी का स्त्रोत है। गाँव के 18 किसान परिवार वर्तमान में बड़ी इलायची की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं तथा फसल उत्पाद को निकटतम बाजार में ₹1000-1200 प्रति किग्रा. की दर से बेच रहे हैं।

माह जुलाई 2015 में इन किसानों को परियोजना से जोड़ा गया। बड़ी इलायची का प्रसार निकटतम परियोजना क्षेत्र में करवाने का निर्णय भी लिया गया। इस हेतु बड़ी इलायची की कलम भी हरीपुर लौंगा गाँव के किसानों से क्रय की गयी।

बड़ी इलायची खेती के विस्तारीकरण के प्रथम चरण में जखोली व

अगस्तमुनि के परियोजना क्षेत्र में 12 उत्पादक समूहों की लगभग 105 महिला किसानों का बड़ी इलायची उत्पादन हेतु चयन किया गया। प्रत्येक महिला किसान ने औसतन 100 पौधों का रोपण माह अक्टूबर 2015 में पूर्ण कर लिया है।

प्रभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई की आगामी योजना के तहत वर्ष 2016-17 में लगभग 800 किसानों को बड़ी इलयची की खेती हेतु प्रेरित किया जायेगा, ताकि जखोली व अगस्तमुनि का परियोजना क्षेत्र बड़ी इलायची के उत्पादन का हब बन सके।

श्री अमन कुमार एवं नागेन्द्र तागवान
तकनीकी समन्वयक-ASEED

प्रभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई
रूद्रप्रयाग, UGVS-ILSP,

जनपद अल्मोड़ा के भिकियासैंण विकासखण्ड में संजीवनी विकास एवं जनकल्याण समिति, रानीखेत के समन्वय से पुष्प उत्पादन कार्य सेनीसेरा, सनरा, कनर्थ एवं अडबोरा गाँव में गठित उत्पादक समूहों के 64 सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है तथा भिकियासैंण गाँव के तीन उत्पादक समूहों (कृष्णा, अंजुमन व खुशी) के 19 सदस्य ऊन आधारित उत्पाद बनाने का कार्य कर रहे हैं।

8 नाली बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया

सफल प्रयोग

मूनाकोट, पिथौरागढ़

पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं आधारभूत सुविधाओं के अभाव तथा शहरों की चकाचौंध से यहाँ लोगों ने बड़ी संख्या में गाँव से शहरों की ओर पलायन किया है। इन परिस्थितियों में जनपद पिथौरागढ़ के मूनाकोट विकासखण्ड के अन्तर्गत गौरीहाट गाँव के निवासी, श्री नैन सिंह जी को गाँव के पास बहने वाली काली नदी के ऊपर वर्षों से बंजर पड़ी लगभग 8 नाली जमीन को उपजाऊ जमीन में बदलने का विचार आया। अपने इस विचार के निष्पादन के लिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने परिवार के सदस्यों एवं कुछ ग्रामवासियों की मदद से जमीन तक आने-जाने लायक रास्ता बनाया। वर्षों से खाली पड़ी जमीन पर पत्थर व झाड़ियों को हटा खेती के अनुरूप बनाने की शुरूआत की, लेकिन पानी की कमी, बंजर जमीन व किसी प्रकार सहयोग न मिलने से उनका ये कार्य पूरा नहीं हो पाया।

इसी बीच एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना ने उत्पादक समूहों के माध्यम से लोगों को परियोजना से जोड़ना प्रारम्भ किया। श्री नैन सिंह ने परियोजना बैठकों में लगातार प्रतिभाग किया। उन्होंने 6 सदस्यों के साथ मिलकर जगन्नाथ पुरूष उत्पादक समूह का गठन किया। समूह ने आजीविका सुधार हेतु संभावनाओं के आधार पर बकरी पालन गतिविधि को प्रथम गतिविधि के रूप में चयनित किया। समूह के सभी सदस्य मनमहेश स्वायत्त सहकारिता के शेयर धारक भी बन गये हैं। समूह सदस्य नियमित रूप से मासिक बैठक तथा प्रतिमाह ₹ 50 की मासिक बचत करने लगे हैं।

परियोजना ने उत्पादक समूहों के क्षमता विकास हेतु विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण, कार्यशाला तथा शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन किया। श्री नैन सिंह तथा उनके समूह के सभी सदस्यों ने

भी इन कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की। अपनी 8 नाली बंजर पड़ी जमीन में सब्जी उत्पादन के लिए उन्होंने सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु मनमहेश स्वायत्त सहकारिता के माध्यम से परियोजना को सिंचाई टैंक का प्रस्ताव दिया। इस टैंक से न सिर्फ उनके खेतों में सिंचाई हुई, बल्कि आसपास के कई अन्य कृषकों के खेतों में भी सिचाई प्रारम्भ हुई। उपयोगिता के आधार पर परियोजना ने समूह को सीमेंट टैंक के निर्माण हेतु ₹ 28,682.00 का वित्तीय सहयोग दिया तथा समूह ने ₹ 5061.00 का अंशदान एकत्रित कर समूह में जमा किया। सभी समूह के सदस्यों की सहमति से सिंचाई टैंक का निर्माण कराया गया है। सिंचाई टैंक का प्रयोग नैनसिंह की जमीन के आस पास के अन्य समूह सदस्यों द्वारा अपनी भूमि के सिंचाई हेतु भी किया जायेगा। सिंचाई की सुविधा हो जाने से श्री नैन सिंह ने अपनी 8 नाली बंजर भूमि को सुधार कर वहाँ सब्जी उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। परियोजना द्वारा श्री नैन सिंह को कृषि विज्ञान केन्द्र, गैना से 1000 प्याज की पौध भी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने अन्य सब्जियों की खेती भी प्रारम्भ की।

इस प्रकार परियोजना के सहयोग से श्री नैन सिंह तथा उनके समूह ने पानी व जानकारी के आधार पर बंजर पड़ी 08 नाली जमीन को उपजाऊ बनाया है। श्री नैन सिंह व जगन्नाथ पुरूष उत्पादक समूह अपने इस कार्य से आस-पास के सभी लोगों के लिए प्रेरणा के स्त्रोत भी बने हैं।

श्री सुभाष चन्द्र सती
सहायक प्रबंधक-PM&E, KM
UGVS-ILSP,पिथौरागढ़

जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति गोसनी द्वारा किये गये विकास कार्य

सफलता

पाटी, चम्पावत

जनपद चम्पावत की ग्राम पंचायत गोसनी जनपद मुख्यालय से लगभग 30 किमी. की दूरी पर स्थित है। राजस्व ग्राम गोसनी के साथ ग्राम परध्यानी भी इस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है। गोसनी में 300 परिवार तथा परिध्यानी में 23 परिवार निवास करते हैं। ग्रामीणों के साथ हुई चर्चा में यह निकल कर आया कि वर्षा आधारित कृषि होने एवं सुअरों का प्रकोप होने के कारण ग्रामवासियों का कृषि के प्रति रूझान दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अथक परिश्रम के उपरान्त भी किसानों को अपने परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है।

जलागम प्रबन्धन इकाई चम्पावत द्वारा एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत गोसनी ग्राम पंचायत को सम्मिलित किया गया। सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक परिदृश्य को जानने के लिए गाँव में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन अभ्यास प्रक्रिया का संचालन किया गया। इस प्रक्रिया से गाँव में विकास हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु निकल कर आये :-

- सिंचाई साधनों की कमी
- उत्पादों को मुख्य मार्ग तक पहुँचने में अत्यधिक कठिनाई
- स्कूली बच्चों को आने-जाने में हो रही असुविधा

ग्राम पंचायत की आम बैठक में ग्रामीणों द्वारा निम्न अन्य प्रस्ताव भी रखे गये :-

- खेतलीगाढ़ में सिंचाई टैंक का निर्माण
- जागोली मन्दिर पुलिया निर्माण
- परिध्यानी गधेरे पर पुलिया निर्माण
- रन्तोला गधेरे पर पुलिया निर्माण
- कापड़ी गाँव में पुलिया निर्माण

ग्राम पंचायत के अन्तर्गत गठित जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त सभी प्रस्तावों पर निर्माण कार्य शुरू कराये गये।

1. **जागोली मंदिर पुलिया निर्माण**- इस पुलिया से 10 परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। महिलाओं तथा बच्चों को आने-जाने में सुविधा प्राप्त हुई। इससे पहले गाँव की महिलाओं को जंगल जाने व स्कूली बच्चों को बरसात में ज्यादा पानी होने के कारण 2 किमी. अतिरिक्त चलकर सुनार गाँव से जाना पड़ता था।
2. **परिध्यानी गधेरे में पुलिया निर्माण**- इस पुलिया निर्माण से 45 परिवार लाभान्वित हुए हैं। परिध्यानी गाँव के ज्यादातर बगीचे व खेत कापड़ी गाँव से लगे हुए हैं। गधेरे में पुलिया न होने से लोगों को फल एवं सब्जी उत्पादों को ढोने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस पुलिया निर्माण के फलस्वरुप फल एव। सब्जी उत्पादन को विक्रय हेतु सड़क व मुख्य बाजार तक ले जाने में सुविधा हुई है।
3. **रन्तोला गधेरे में पुलिया निर्माण**- रन्तोला नाले में पानी भरने से गोसनी गाँव की सभी महिलाओं को जंगल आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पुलिया निर्माण होने से लोगों के जंगल एवं बाजार आवागमन में आसानी हुई है।
4. **कापडी गाँव पुलिया निर्माण**- कापड़ी गधेरे में पानी भरने से ग्रामवासियों व स्कूली बच्चों को सुनार गाँव से होकर जाना पड़ता था, लगभग 1200 मीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी।

पृष्ठ 2 का शेष-

परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ

पुलिया निर्माण से स्कूली बच्चों व गाँव के लोगों को सुविधा मिली है।

परियोजना द्वारा उत्पादक समूहों का गठन कर ग्रामवासियों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्जी उत्पादन हेतु प्रेरित किया गया है। उत्पादक समूहों के सदस्यों को उन्नत बीज व खाद भी उपलब्ध कराये गये। परिणामस्वरूप टमाटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी तथा बन्दगोभी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। परिध्यानी एवं गोसनी गाँव में टमाटर, शिमला मिर्च व बन्द गोभी की खेती कर उत्पादन एवं विपणन किया गया है। परिध्यानी गाँव में 4 परिवारों ने सब्जी उत्पादन किया, जिससे उन्हें ₹16,000.00 से ₹ 50,000.00 तक की आय हुई। गोसनी गाँव में 5 परिवारों ने सब्जी उत्पादन किया, जिससे उन्हें ₹ 18,000.00 से ₹ 52,000.00 तक की आय हुई। इस प्रकार उत्पादक समूह के सदस्यों की आजीविका में वृद्धि हुई है।

परियोजना द्वारा प्रदान किये गये सहयोग से ग्रामीणों की आय में जहाँ आशानुरुप वृद्धि हुई है, वहीं लोगों में परियोजना के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। उत्पादक समूह के सदस्यों द्वारा गाँव के अन्य लोगों को भी कलस्टर खेती तथा परियोजना से लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

कु. सरोज उप्रेती, सुगमकर्ता
प्रभाग-चम्पावत, ILSP-WMD

- साथ ही 16 गाँव के 900 किसानों को उच्च गुणवत्ता एवं अधिक उत्पादन वाले गिरीदार फलों के पौधे, कीवी, स्ट्रॉबरी एवं बड़ी इलायची के पौधे प्रदान कर मॉडल बगीचों की स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड के समन्वय से परियोजना क्षेत्र में पशुनस्ल सुधार व प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु 58 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र स्थापित तथा 6 का कार्य प्रगति पर।
- पशुपालन विभाग, अल्मोड़ा के समन्वय से भैंसवाड़ा फार्म को पशुचारे के लिए 'सेंटर फॉर एक्सीलेंस' बनाने हेतु कार्य प्रगति पर।
  - → सामुदायिक चारा फार्म विकसित करने कार्य प्रगति पर।
  - → चारा बीज बैंक विकसित करने का कार्य प्रगति पर।
  - → भैंसवाड़ा फार्म से 5 विकासखण्डों के 50 गाँवों के 900 लाभार्थी जुड़कर चारा उत्पादित करने कार्य करेंगे।
- पशुपालन विभाग, टिहरी द्वारा जौनपुर, चम्बा एवं फकोट क्षेत्र में पशुचारा विकास हेतु उत्पादक समूहों के 650 सदस्यों के साथ 3885 चारा प्रजाति एवं 133.7 कुं. नैपियर रोपण का कार्य प्रगति पर। इसके साथ ही किसानों को मिनी कृषि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।
- संजीवनी विकास एवं जनकल्याण समिति, रानीखेत द्वारा भिकियासैंण, अल्मोड़ा 4 गाँवों के 83 उत्पादक समूह के सदस्यों के साथ पुष्प उत्पादन एवं ऊन आधारित उत्पाद निर्माण का कार्य प्रगति पर।
- जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी द्वारा जनपद अल्मोड़ा एवं देहरादून के 7 गाँवों में उत्पादक समूहों के 1500 सदस्यों के साथ पॉलीहाउस व शेडनेट के माध्यम से उन्नत उद्यानिकी तकनीकी आधारित लाइवलीहुड मॉडल बनाने का कार्य क्रियान्वित।

4 रोजगारपरक व्यवसायिक प्रशिक्षण

- प्रथम चरण में जनवरी 2014 से मार्च 2015 तक 11 ट्रेडों में 5 जनपदों के 26 ब्लॉकों के 688 युवक/युवतियों को प्रशिक्षित किया गया। कुल प्रशिक्षणार्थियों में से 570 युवक/युवतियों को जॉब हेतु प्रस्ताव मिला तथा कुल 318 युवक/युवतिओं ने यह प्रस्ताव स्वीकार किए।
- दूसरे चरण में वर्ष 2015-16 में 1000 युवाओं को 54 ट्रेडों में प्रशिक्षित करने की परियोजना की योजना है, इस हेतु कौशप्रदाता एंजेसियों का चयन कर मोबलाईजेशन का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

परियोजना समिति जलागम प्रबंध निदेशलय (PS-WMD) द्वारा परियोंजना के घटक-2 सहभागी जलागम विकास का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जल एवं जलागम प्रबंधन समिति

- इसके अन्तर्गत 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के 70194 है0 क्षेत्र में 187 ग्राम पंचायतों की सहभागिता के माध्यम से जलागम विकास योजना हेतु 148 'जल एवं जलागम प्रबंधन समिति' गठित की गई है। इन गठित समितियों के माध्यम से सहभागी जलागम विकास का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

परियोजना के अन्तर्गत रोजगारपरक व्यवसायिक प्रशिक्षण

परियोजना के प्रथम घटक खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि के अन्तर्गत सन् 2019 तक राज्य के 15000 युवाओं को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। परियोजना द्वारा कुल लक्षित युवाओं में से 60% युवतियों को प्रशिक्षित करना है। कुल प्रशिक्षित युवाओं में से 80% हेतु जॉब प्लेसमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के किसी भी पर्वतीय समुदाय के युवक/युवतियाँ इन व्यवसायिक प्रशिक्षणों का लाभ उठा सकते हैं।

प्रशिक्षण का प्रथम चरण

परियोजना द्वारा प्रथम चरण में जनवरी 2014 से मार्च 2015 तक 6 कौशलप्रदाता एजेंसियों के माध्यम से 11 ट्रेड्स को चिन्हित कर 5 जनपदों टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा व बागेश्वर के 26 ब्लॉकों के 688 युवक/युवतियों को प्रशिक्षित किया गया। कुल प्रशिक्षणार्थियों में से 570 युवक/युवतियों को जॉब हेतु प्रस्ताव मिला तथा कुल 318 युवक/युवतिओं ने यह प्रस्ताव स्वीकार किए जो कि खाद्य एवं पेय उद्योग, अस्पतालों, बी.पी.ओ.दवा कम्पनियों, मोबाइल रिपेयरिंग इकाईयों, प्रशिक्षण संस्थानों, आदि में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, बंगलुरू, पंचकुला चंडीगढ़, उत्तरकाशी, दिल्ली, ऋषिकेश आदि जगहों पर कार्यरत हैं।

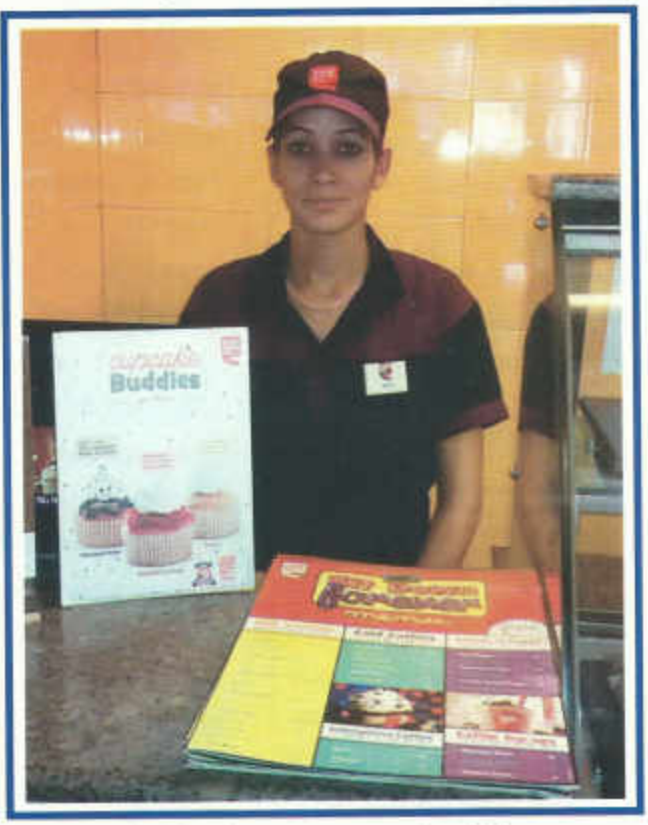

प्रशिक्षण का दूसरा चरण

प्रथम चरण के अनुभवों के आधार पर द्वितीय चरण के प्रशिक्षण की रणनीतियाँ बनाकर व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने की योजना बनाई गई। सभी प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप NCVT/SSCS/NSDC द्वारा तय पाठ्यक्रमों के अनुरूप सम्पादित होंगे। प्रशिक्षण के उपरांत NCVT/SSCS/NSDC के अनुरूप प्रशिक्षण सार्टिफिकेट प्रदान किये जायेंगे। वर्ष 2015-16 में परियोजना 1000 युवाओं को 54 ट्रेडों में प्रशिक्षित करायेगी, जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार से हैं-

- प्रशिक्षण हेतु परियोजना क्षेत्र से गाँव के स्थानीय समूहों, फैडरेशनों, आजीविका संगठनों की मदद से जरूरतमंद अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
- दुर्गम, ग्रामीण अंचलों के आर्थिक रूप से कमजोर और किसी भी तरह से अशक्त युवक/युवतियों को वरीयता दी जायेगी।
- प्रशिक्षणों में 60 प्रतिशत युवतियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
- प्रशिक्षण हेतु चयन एंट्री लेवल टेस्ट के आधार पर होगा।
- प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 साल होनी आवश्यक है।

- प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का 75% अंश परियोजना तथा 25% अंश प्रशिक्षणार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।
- बाजार एवं अभ्यर्थियों की मांग के आधार पर प्रशिक्षण सुविधा।
- पाठ्यक्रम के अनुरूप आवासीय और गैर आवासीय दोनों तरह के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी भी आकस्मिक घटना से निपटने हेतु बीमा की सुविधा उपलब्ध होगी।
- प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को सॉफ्ट स्किल्स डवलपमेंट व इनफॉरमेशन टैक्नोलॉजी का ज्ञान भी प्रदान किया जायेगा।
- प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को यौन शोषण पर संवेदनशील बनाने हेतु आवश्यक पाठ्यक्रम होगा।
- प्रशिक्षण के बाद 80% युवाओं को न्यूनतम परिश्रमिक पर रोजगार का प्लेसमेंट उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रशिक्षण के बाद कौशलप्रदाता एजेंसियों के माध्यम से रोजगार के बाद 1 साल तक फॉलो-अप की आवश्यक व्यवस्था होगी।

परियोजना के मुख्य हस्तक्षेपों में सोशल मोबिलाईजेशन, युवाओं

की काउंसलिंग व मोबिलाईजेशन स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग व सर्टिफिकेशन, प्लेसमेंट फैसिलिटेशन व प्लेसमेंट मॉनीटिरिंग प्रकियाएं शामिल हैं। सोशल मोबलाईजेशन और चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता की गहन काउंसलिंग की जायेगी।

द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रमों (लगभग 52 ट्रेड) की शुरूआत की जा चुकी है। प्रशिक्षण हेतु निम्न एंजेसियाँ चयन की गई हैं, जो कि प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, तकनीकी एंजेसी, आजीविका संगठन, फैडरेशन व समूहों के सहयोग से अभ्यर्थियों का चयन करेंगी-

1 एस.जी.आर.एस. एकेडमिक प्रा.लि., रांची
2 मानव विकास एवं सेवा संस्थान, लखनऊ
3 श्री वैश्नो एजुकेशनल सोसायटी, दिल्ली
4 यूनिफायरस सोशियल वैन्चर्स प्रा.लि., दिल्ली
5 डी.ए.वी.-आई.टी.सी., दिल्ली
6 वी.ए.पी. टैक्नोलॉजी, हल्द्वानी
7 माऊंट टैलेंट कंलसल्टिग, नोएडा
8 उपकार कल्याण समिति, हल्द्वानी
9 मास इन्फोटैक सोसायटी, यमुनानगर
10 जी. एंड जी. एजुकेशन सोसायटी, चंडीगढ़
11 राणा शिक्षा समिति, यमुनानगर
12 आई. एल. एफ. स्किल डवलेपमेंट कारॅपोरेशन लि., दिल्ली
12 वॉकमैन इण्डिया, प्रा.लि., दिल्ली
13 देव ऋषि एजुकेशनल सोसायटी, देहरादून
14 श्रेष्ठा फांऊडेशन, हल्द्वानी
15 लॉर्ड गणेशा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टैक्नोलॉजी, मोहाली
16 बी.-ऐबल, दिल्ली
17 नेशनल पैरामैडिकल साईंस सोसायटी, यमुनानगर
18 डिवाईन इंटरनेशनल फांऊडेशन, हरिद्वार
19 त्रिहुत समग्र विकास परिषद, देहरादून
20 बाबा साहेब अम्बेडकर टैक्निकल एजुकेशनल सोसायटी, दिल्ली

रोजगारपरक व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवक/युवती अपने जनपद की प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, तकनीकी एंजेसी, आजीविका संगठन/फैडरेशन से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री राजीव सिंघल
प्रबंधक: P/M&E,
UGVS-ILSP

चौलाई उत्पादन बना आय का साधन

भटवाड़ी, उत्तरकाशी

श्रीमती सुमित्रा देवी ग्राम दंदाल्का की निवासी है। ग्राम दंदाल्का जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत आता है। दंदाल्का गाँव में परियोजना द्वारा तकनीकी संस्था ए.टी.आई. के माध्यम से ब्रह्मकमल उत्पादक समूह का गठन किया गया है। सुमित्रा देवी को समूह की अध्यक्ष चुना गया। सुमित्रा देवी एक गरीब व साधारण परिवार की महिला हैं। इनके पति श्री हरदेव सिंह रोजी-रोटी के लिये स्थानीय मजदूरी व डोडीताल जाने वाले पर्यटकों के साथ उनका सामान ढोने का कार्य करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सुमित्रा देवी ने सब्जी उत्पादन आरम्भ किया, परन्तु बाजार दूर होने के कारण वह समय पर सब्जियों को बाजार तक नहीं पहुँचा पाती थी, जिससे उनकी मेहनत बेकार चली जाती थी।

परियोजना की तकनीकी संस्था के कार्यकर्ताओं ने सुमित्रा देवी को चौलाई उत्पादन करने का सुझाव दिया कि इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ चौलाई उत्पादन के लिये अनुकूल हैं। कार्यकर्ताओं के सुझाव के अनुसार उन्होंने 10 नाली भूमि में चौलाई उत्पादन प्रारम्भ किया। परियोजना द्वारा दी गई सहयोग राशि से सुमित्रा देवी ने छोटे स्प्रे हैण्ड पम्प खरीदे। प्राप्त जानकारी के अनुरूप जैविक कीटनाशक का उपयोग कर अपनी फसल को कीटों से बचाया तथा फसल उत्पादन को बेहतर बनाने हेतु समय-समय पर प्राप्त तकनीकी जानकारी का उपयोग किया, जिससे चौलाई की अच्छी फसल हुई। 10 नाली भूमि में कुल 4.5 कुं. चौलाई का उत्पादन हुआ, जिसमें से कुल 4 कुं. चौलाई का ₹ 22,000.00 का विपणन किया। इससे सुमित्रा देवी को ₹ 18,000.00 का शुद्ध लाभ हुआ।

वर्तमान में सुमित्रा देवी चौलाई के साथ-साथ झंगोरा, मंडुआ, राजमा व आलू की खेती भी कर रही हैं। सुमित्रा देवी परियोजना के सहयोग से बहुत उत्साहित हैं तथा भविष्य में चौलाई की खेती को वृहद स्तर पर करने की सोच रही हैं।

श्री रविन्द्र सिंह पंवार
आजीविका सुगमकर्ता, तकनीकी संस्था-ए.टी.आई.
UGVS-ILSP, उत्तरकाशी

दीपा की अभिलाषा को मिला परियोजना का सहयोग

मूनाकोट, पिथौरागढ़

सफलता

गाँव कुसेरी, जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट का एक दूरस्थ ग्राम है। डेयरी एवं कृषि, यहाँ के काश्तकारों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत है। इस गाँव की श्रीमती दीपा सौन सब्जी उत्पादन के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका अर्जित करती हैं। दीपा सौन द्वारा किये जा रहे कार्यों को देख व उनके साथ चर्चा कर ज्ञात हुआ कि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया। कम उम्र में विवाह होने के कारण वह हाईस्कूल तक ही शिक्षा ग्रहण कर पायीं।

उनकी इच्छा समाज में अपनी अलग पहचान बनाने की थी। उन्होंने क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था निधि से सम्पर्क कर गाँव में एक समूह का गठन किया। सभी सदस्यों ने प्रति माह ₹25.00 की बचत करना प्रारम्भ की, लेकिन समूह की आयअर्जक गतिविधि न होने के कारण समूह मात्र पैसा जमा करने तक ही सीमित रहा और जल्दी ही बिखर गया। दीपा अपने प्रयास के विफल होने के कारण काफी निराश हुई, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरीश चन्द्र जोशी के प्रेरित करने पर उन्होंने आशा कार्यकर्त्री के पद हेतु आवेदन किया और उनका चयन हो भी गया। वर्तमान में वह गाँव में व आस-पास के क्षेत्रों में एक सफल आशा कार्यकर्त्री के रूप में अपने पहचान स्थापित कर चुकी हैं।

दीपा को जब एकीकृत आजीविका के संबंध में ज्ञात हुआ तो उन्होंने ग्राम प्रधान से परियोजना के बारे पता किया। इसके बाद दीपा सौन ने स्वयं परियोजना की तकनीकी संस्था सीबेड के कोऑर्डिनेटर व कार्यकर्ताओं से सम्पर्क किया व उन्हें अपने गाँव में बैठक कर समूह गठन करने हेतु आमंत्रित किया।

तकनीकी संस्था सीबेड के कार्यकर्ताओं ने कुसेरी गाँव में बैठक कर उपस्थित लोगों को परियोजना की विभिन्न गतिविधियों व उत्पादक समूह के गठन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। परिणामस्वरुप कुसेरी गाँव में तीन उत्पादक समूहों, क्रमशः लक्ष्मी उत्पादक समूह, गंगा उत्पादक समूह तथा नौला उत्पादक समूह का गठन किया गया। इन समूहों से गाँव के कुल 26 परिवार सदस्य के रूप में जुड़े। तीनों समूह के सदस्य ₹50.00 मासिक की बचत भी कर रहे हैं। परियोजना द्वारा सब्जी उत्पादन (टमाटर) के लिये लक्ष्मी, डेयरी के लिए गंगा तथा धान उत्पादन के लिए नौला उत्पादक समूह को प्रथम वर्ष की सहयोग राशि प्रदान की गई,, जिसका उपयोग समूह सदस्यों द्वारा बीज, कीटनाशक, आदि क्रय करने में किया गया है।

दीपा सौन सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में नये-नये प्रयोग करके समूह सदस्यों को आजीविका संवर्धन हेतु प्रेरित भी कर रही हैं। उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप क्षेत्र के सभी समूह सदस्य अपने-अपने खेतों में टमाटर की खेती कर रहे हैं। दीपा स्वयं भी टमाटर एवं बन्दगोभी की खेती कर रही है, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष लगभग ₹ 25,000 से ₹ 30,000 तक की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इस वर्ष गाँव में टमाटर का उत्पादन लगभग 5 कु. तक होने की संभावना है, जिसे बेचकर समूह की महिलाओं की आजीविका में अवश्य सुधार आयेगा।

श्री हरीश सिंह टोलिया
फील्ड फेसिलिटेटर,
सीबैड, मूनाकोट

श्री राजेश मठपाल
सहायक प्रबन्धक मार्केट एक्सेस
प्रभागीय प्रबंधन इकाई, पिथौरागढ़

सफल डेयरी व्यवसाय ने बदली ग्राम की तस्वीर

सल्ट, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड के पर्वतीय अंचल के कई क्षेत्र वर्तमान में भी विकास की मुख्यधारा से अछूते हैं। जनपद का सल्ट विकासखण्ड भी विकास की मुख्य धारा से वर्तमान तक नहीं जुड़ पाया है। इस विकासखण्ड का बेसरबगड़ ग्राम मुख्य सड़क मार्ग से लगभग 4 किमी. की दूरी पर है। बेसरबगड़ ग्राम में 96 परिवार निवास करते हैं। कुछ समय पूर्व तक ग्राम में खेती ही आजीविका का मुख्य साधन था। लेकिन वर्तमान में जंगली जानवरों के अत्यधिक प्रकोप एवं सिंचाई की सुविधाओं की कमी के कारण खेती से समुदाय विमुख होता जा रहा है। गाँव से नौजवानों के पलायन का यह भी एक मुख्य कारण रहा है।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से समुदाय द्वारा वर्तमान में मसाला एवं दुग्ध उत्पादन गतिविधि को सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा रहा है। बेसरबगड़ ग्राम में डेयरी गतिविधि शुरू करने में प्रारम्भिक दौर में निम्न मुख्य चुनौतियाँ रहीं :-

- ग्राम की सड़क मार्ग से दूरी, सिंचाई एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव।
- विपणन सुविधा का अभाव।
- परम्परागत तरीकों का प्रयोग एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव
- रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास का बोलबाला।
- पर्याप्त मात्रा में निवेश हेतु पैसे का अभाव।
- जानवरों हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव।
- प्राकृतिक आपदा।

परियोजना द्वारा बेसरबगड़ ग्राम में कुल 7 उत्पादक समूहों का गठन किया गया। पूर्व से ही की जा रही गतिविधियों के संबंध में समूहों के साथ गहन विचार-विमर्श कर चयन किया गया। गठित उत्पादक समूहों के 68 सदस्यों को कुल ₹ 4,89,600.00 की धनराशि परियोजना सहयोग के रूप में डेयरी गतिविधि आरम्भ करने हेतु उपलब्ध कराई गई। परियोजना के मार्गदर्शन में सदस्यों द्वारा डेयरी गतिविधि हेतु आवश्यक विभिन्न साधन जैसे- चारा नाद, चैफकटर, गोठ सुधारीकरण, दुधारू पशु क्रय, दूध केन एवं चारा पौध रोपण आदि कार्य किये गये। सूक्ष्म आकार के नूतन चैफकटर

उपलब्ध करवाये गये, जिनको समुदाय ने सराहा। साथ ही समूह सदस्यों को नैपियर एवं अन्य घासों के विस्तारीकरण हेतु भी प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक मुश्किल कार्य समुदाय में प्रचलित अंधविश्वास -'दूध बेचने से जानवर का दूध सूख जाना एवं ग्राम में किसी अनहोनी का होना' के प्रति लोगों को जागरूक करना था। जागरूकता के कार्य में ग्राम के श्री दीवान सिंह एवं अध्यापक श्री कुन्दन सिंह का सराहनीय योगदान रहा। दोनों ही व्यक्तियों ने अपने घर से दूध बेचने की शुरूआत की। उनके द्वारा शुरूआत करने से गाँव में धीरे-धीरे सभी पशुपालकों ने दूध बेचना आरम्भ किया। इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, नैरोबी की पशु चिकित्सक डॉ. थानामल का योगदान रहा।

परियोजना द्वारा दुग्ध विपणन हेतु आंचल दुग्ध सहकारिता से समन्वय कर गाँव में दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित कराया गया। आंचल द्वारा समूहों को मिल्क केन, मापन हेतु लीटर एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवायी गई हैं। वर्तमान में इस केन्द्र के माध्यम से लगभग 80 लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया जा रहा है, साथ ही लगभग 20 लीटर दूध स्थानीय बाजार में भी बेचा जा रहा है। इस प्रकार डेयरी गतिविधि के माध्यम से शुरूआत में प्रत्येक परिवार मासिक रूप से ₹ 900.00 की औसत आय प्राप्त कर रहा है।

डेयरी व्यवसाय के दौरान दुधारू जानवरों की स्वास्थ्य जाँच, दवाईयों की उपलब्धता एवं समय-समय पर होने वाला टीकाकरण आदि भी आवश्यक हैं। अत: परियोजना द्वारा ग्राम के ही एक बेरोजगार एवं जुझारू नौजवान श्री दीवान सिंह (जगदम्बा उत्पादक समूह) को पैरावेट प्रशिक्षण हेतु ऋषिकेश में उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद के माध्यम से 3 माह का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया। प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरान्त दीवान सिंह द्वारा न सिर्फ अपने ग्राम वरन् आसपास के ग्रामों में भी पशुपालकों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तथा समुदाय को उन्नत तरीके से पशुपालन हेतु भी जागरूक किया जा रहा है।

परियोजना द्वारा समुदाय के सहयोग से बेसरबगड़ ग्राम में आरम्भ की गयी इस पहल के परिणाम निम्न प्रकार परिलक्षित हुए :

- उत्पादक समूह गठन के माध्यम से ग्राम में सहभागिता की भावना बढ़ी है।
- समुदाय को डेयरी व्यवसाय के रूप में सतत् आजीविका के साधन प्राप्त हुआ।
- डेयरी व्यवसाय के माध्यम से समुदाय की आजीविका के साधन में बढ़ोत्तरी हुई।
- समुदाय ने डेयरी व्यवसाय के उन्नत तरीके सीखे।
- मुख्यत: महिलाओं के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में बढ़ोत्तरी हुई।
- गाँव में प्रचलित अंधविश्वास एवं रूढ़ियों को समाप्त करने में सफलता मिली।
- उत्पादक समूह के सदस्यों के कौशल में वृद्धि हुई।
- डेयरी व्यवसाय को आधुनिक तरीके से सम्पादित करने के परिणामस्वरूप महिलाओं के कार्यबोझ में कमी हुई।
- पैरावेट के माध्यम से पशुपालकों को जानवरों के स्वास्थ्य एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा।
- उत्पादक समूह सदस्यों को पैरावेट, दूध ढुलान, संग्रहणकर्ता, दुग्ध समिति सचिव के रूप में अल्प रोजगार की उपलब्धता।
- डेयरी व्यवसाय की सफलता को परियोजना के समीक्षा दलों द्वारा भी देखा गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि डेयरी व्यवसाय के माध्यम से ग्राम समुदाय के आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में अल्प मात्र में ही सही लेकिन सतत्ता के प्रयास के साथ प्रगति हो रही है।

श्री नितेश पंत, परियोजना सहायक
प्रभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई, अल्मोड़ा
UGVS-ILSP

परियोजनान्तर्गत प्रकाशित दस्तावेज

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति द्वारा परियोजना अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाओं एवं ज्ञान के आदान-प्रदान करने तथा समुदाय के क्षमता विकास के लिए दस्तावेजों का संकलन कर प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित दस्तावेजों का विवरण निम्न प्रकार से है-

- एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के प्रचार-प्रसार एवं समुदाय में जागरूता बढ़ाने के उद्देश्य से 10 मिनट की एक 'डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म'
- रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित 27 कार्यरत युवाओं के सफल केस अधययनों को संकलन 'उड़ान'
- फैडरेशनों/उत्पादक समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन हेतु 'हिलांस स्टीकर'
- परियोजना परिचय ब्रोशर
- उत्पादक समूहों एवं आजीविका संगठनों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल- 'सुशासन, विपणन योजना, व्यावसायिक योजना'
- उत्पादक/निर्बल उत्पादक समूह एवं आजीविका संगठन आधारित 'सामुदायिक संगठन बुकलेट'
- सरकार द्वारा संचालित की विभिन्न योजनाओं पर आधारित- 'ज्ञान दिगदर्शिका बुकलेट'
- समुदाय में जागरूकता के लिए विभिन्न विषयों (पशुपालन, महिला सशक्तीकरण, आजीविका संगठन, विपणन से सम्बन्धित '6 पोस्टर'
- उत्तराखंड की परंपरागत फसलों के उत्पादन से लेकर उपभोग तक को बढ़ावा देने व इन उत्पादों की पोषकता के प्रचार-प्रसार हेतु 'बारहनाजा बुकलेट' तथा 'पोस्टर'
- ग्रामीण उद्यमों से आजीविका बढ़ाने हेतु किये जा रहे प्रयासों एवं अनुभवों का संकलन 'A Quiet Journey' अंग्रेजी में एवं हिन्दी में 'खामोश यात्रा'

ज्ञान प्रबंधन, UGVS-ILSP

सहकारिता के लिए आर्थिकी का नया साधन इन्दिरा अम्मा भोजनालय

गोपेश्वर, चमोली

गतिविधि

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में समाज के गरीब एवं जरुरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में सस्ते भोजन की कैन्टीन की व्यवस्था 'इन्दिरा अम्मा भोजनालय' नाम से की गई है। दिनांक 19 नवम्बर 2015 को प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 'इन्दिरा अम्मा भोजनालय' का शुभारम्भ किया गया।

इस योजना का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आर्थिक रुप से सशक्त करने का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करवाना है। भविष्य में इस कार्यक्रम की सफलता को विकासखण्ड स्तर तक पहुँचाया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधि प्रदान की जा सके।

जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में 'भोजनालय' का संचालन परियोजना द्वारा सहायतित 'पर्वतीय कृषि विपणन स्वायत्त सहकारिता' द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मा. मंत्री शहरी विकास, उत्तराखण्ड सरकार श्री प्रीतम पंवार द्वारा किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए., नगरपालिका अध्यक्ष एवं समस्त रेखीय विभागों के अधिकारी एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्य उपस्थित रहे।

दिनांक 01.09.2015 को मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. के साथ हुई बैठक के दौरान इन्दिरा अम्मा भोजनालय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई तो इस सम्बन्ध में परियोजना द्वारा पर्वतीय कृषि विपणन स्वायत्त सहकारिता, घिंघराण की अध्यक्ष श्रीमती सुरमा देवी व अन्य सदस्यों से इन्दिरा अम्मा भोजनालय संचालन के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। सहकारिता की सहमति के उपरान्त प्रति थाली लागत मूल्य का आकलन कर मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. को अवगत कराया गया। उक्त आकलन में समस्त सामग्री बाजार से ही क्रय की जानी थी जिस पर प्रति थाली लागत ₹ 50.00 आ रही थी। दिनांक 29.10.2015 को सचिवालय स्तर पर आयोजित वीडियों कान्फ्रैंसिंग के दौरान प्रमुख सचिव महिला सशक्तीकरण

एवं बाल विकास श्रीमती राधा रतूड़ी को उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तो उनके द्वारा जनपद के जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इन्दिरा अम्मा भोजनालय हेतु कार्यदायी संस्था को ए.पी.एल. श्रेणी की दर से गेंहू एवं चावल माँग अनुसार उपलब्ध करायें।

सहकारिता ने सोचा कि ₹ 5.00 प्रति थाली सर्विस चार्ज लेकर यदि हम प्रतिदिन 100 थाली बेचेंगे तो प्रतिदिन ₹ 500.00 शुद्ध आय होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली ₹ 20.00 की सब्सिडी दी जा रही है। सहकारिता ने माह नवम्बर से मार्च 2016 तक ₹ 29622.00 का लाभ कमाया है।

इन्दिरा अम्मा कैन्टीन/भोजनालय मासिक लाभ/हानि विवरण

माह का नाम	कुल आय	कुल व्यय	लाभ/हानि	सब्सिडी से प्राप्त आय	शुद्ध लाभ/हानि
नवम्बर 2015	24645	31310	-6665	8035	1370
दिसम्बर 2015	44495	58121	-13626	17700	4074
जनवरी 2016	62900	66299	-3399	22290	18891
फरवरी 2016	43625	53071	-9446	17450	8004
मार्च 2016 (1 से 15 मार्च तक)	23850	26107	-2257	9540	7283
योग	**199515**	**234908**	**-35393**	**75015**	**39622**

यद्यपि प्रथम माह में शुद्ध लाभ का आंकड़ा कम है, परन्तु इसका सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिला है। एक ओर जहाँ कैंटीन से 6 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, वहीं दूसरी ओर स्वयं सहायता समूहों से झंगोरा, मंडुवा, सब्जियाँ, राजमा, गहत, उड़द, भट्ट आदि को क्रय किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर एव बाजार तैयार हो रहा है। साथ ही आम नागरिक को साफ सुथरा, पौष्टिक व सस्ता भोजन उपलब्ध हो रहा है। कैंटीन संचालन से संतुष्ट होकर जिलाधिकारी ने टी.एच.डी.सी. को कैंटीन हेतु वॉटर प्योरी-फायर देने को कहा है।

प्रभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई
UGVS-ILSP, चमोली

ज्ञानवर्धन लेख

पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी इलायची की खेती की अपार सम्भावनाएँ

मसालों में बड़ी इलायची का प्रमुख स्थान है। मसालों के अतिरिक्त इसका उपयोग आयुर्वेदिक तथा ऐलोपेथिक औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। इससे एक प्रकार का तेल निकाला जाता है जिसे नेत्र रोग में उपयोग किया जाता है। इसके बीज हृदय व यकृत के लिए टॉनिक का कार्य करते हैं। इसकी बढ़ती माँग व बहुमूल्य उपयोग के कारण इसके उत्पादन की सम्भावना बढ़ती जा रही है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियाँ इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों के नम एवं छायादार बाग इसकी खेती के लिए उपयुक्त हैं। अत: इन क्षेत्रों में बड़ी इलायची का उत्पादन कर लाभ कमाया जा सकता है, साथ ही यह कई लोगों की आजीविका का साधन भी बन सकती है।

जलवायु : बड़ी इलायची की खेती के लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु चाहिए। समुद्र तल से 600 से लेकर 2000 मीटर की ऊँचाई वाले स्थान इलायची की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। सघन खेती के लिए छायादार वृक्षों से घिरी हुई ढालू जमीन अधिक उपयुक्त रहती है। अच्छी वृद्धि एवं पैदावार के लिए कम तापक्रम तथा 250 सेमी. से 380 सेमी. वार्षिक वर्षा उपयुक्त रहती है। लेकिन इसकी सफल खेती के लिए 50% छाँव आवश्यक है।

भूमि : बड़ी इलायची की अच्छी खेती के लिए बलुई दोमट मिटटी से युक्त भूमि, नम दोमट जिसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में हो तथा जल निकास का समुचित प्रबन्ध हो, अधिक उपयुक्त रहती है। अम्लीय पी.एच. तथा कार्बनिक यौगिकों से युक्त भूमि बड़ी इलायची की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम होती है।

उन्नत प्रजातियाँ : इलायची की अच्छी पैदावार लेने के लिए उपयुक्त प्रजाति का चुनाव करना चाहिए। प्रजाति का चयन ऊँचाई के अनुसार करना चाहिए। इलायची की अच्छी पैदावार के लिए प्रमुख प्रजातियाँ हैं-

क्र.सं.	समुद्रतल से ऊँचाई	
प्रजाति		
1	600-1100 मी.	जेंगू गोलसे
2	1100-1500 मी.	साबने

उक्त प्रजातियों के अतिरिक्त रामसे, रामनाग व लोकल ज्योलीकोट प्रजातियाँ भी हैं, जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं। इन प्रजातियों को घाटियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।

भूमि की तैयारी : सर्वप्रथम जमीन की जुताई कर पत्थर आदि दूर कर लिए जाते हैं तथा सड़ी हुई गोबर की खाद ह्यूमस या कम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट तथा जैव फफूंदीनाशक को मिट्टी में मिला लिया जाता है। फिर मिट्टी में 1.5 मी. X 1.5 मी. की दूरी पर 2 X 2 X 2 फीट के गड्ढे बनाये जाते हैं। गड्ढे अप्रैल व मई में खोदने चाहिए। साधारणत: पौधों के बीच की दूरी इलायची की किस्म पर निर्भर करती है। यह दूरी विभिन्न किस्मों में निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	प्रजाति	पौधों की दूरी (मी.)
1	जेंगू गोलसे, साबने, वारलन्गें, रामसे	1.5 x 1.5
2	रामनाग	1.2 x 1.2
3	स्थानीय ज्योलिकोट	1.0 x 1.0

अलग-अलग दूरी के आधार पर प्रति नाली 50-80 पौध/सकर्स (प्रति हेक्टेयर 2500-4000 सकर्स की आवश्यकता होती है।

रोपण : इलायची के अच्छे उत्पादन के लिए सकर्स को जुलाई माह में लगाना चाहिए। इसको लगाने के लिए बादलों से घिरा हुआ मौसम उपयुक्त रहता है। तैयार गड्ढों में सकर्स लगाने के उपरान्त आसपास की मिट्टी से दबा दिया जाता है। पौधा लगाने के बाद पौधों की जड़ पर पत्तियाँ या फूस इत्यादि से मल्च/पलवार कर देनी चाहिए। इससे जमीन की ह्यूमस क्षमता बढ़ती है और जमीन में नमी भी बनी रहती है। साथ ही खरपतवार भी कम मात्रा में निकलते हैं, जिससे पौधों की जड़ों का विकास भी अधिक होता है।

खाद : खाद की मात्रा जमीन के प्रकार पर निर्भर करती है। अलग-अलग जमीन में अलग-अलग खाद की मात्रा की आवश्यकता होती है। खेती की तैयारी के समय 200-400 कुं. गोबर की खाद प्रति हे0 (50 नाली) में आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अच्छे उत्पादन के लिए 20-40 किग्रा. नाईट्रोजन, 25-30 किग्रा. फॉस्फोरस और 40-50 किग्रा. पोटाश की आवश्यकता प्रति वर्ष होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा भी जैविक खाद के स्त्रोत से देनी चाहिए।

देखभाल : बड़ी इलायची के पौधों को लगाने के 3-5 वर्ष पश्चात् फूल तथा फल आने प्रारम्भ हो जाते हैं। फलों के समुचित वृद्धि के लिए समय-समय पर घास निकालते रहना चाहिए जिससे एक कन्द में अधिक कोपले होने पर कन्द को धूप व हवा आसानी से उपलब्ध हो सके तथा अन्य औद्योगिक क्रियाएं एवं पौध प्रसारण होने में भी सरलता हो सके। प्रथम बार फरवरी या मार्च माह में सफाई करनी चाहिए। दूसरी बार मई में, तीसरी बार फल तोड़ने से पहले करनी चाहिए। अधिक धूप वाले मौसम में पौधों को झुलसने से बचाने के लिए उन्हें सूखी पत्तियों या कृषि फसल अवशेष से ढकना लाभकारी रहता है।

कीटों एवं बीमारियों की रोकथाम :बड़ी इलायची के मुख्यतया: विषाणु जनित रोग लगते हैं जिसमें कुछ रोग एवं बचाव के तरीके निम्नलिखित हैं-

रोग	पौधों के बचाव हेतु ध्यान रखने योग्य बातें
• फुर्की विषाणु जनित • चिर्को विषाणु जनित • कन्द में सड़न	• रोग प्रतिरोध किस्म का चयन करना चाहिए। • कीटों के आक्रमण से पौधों को बचाना चाहिए। • मातृ पौधों में शाखाओं वाली कोपलों की संख्या अधिक होनी चाहिए। • कैप्सूल, आकार में बड़ा होना चाहिए। • खेतों को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए।

फलों की तुड़ाई : बड़ी इलायची से प्रथम फसल इसके रोपण के 3-4 वर्षों के बाद मिलती है। फलों को तोड़ने का कार्य अगस्त माह से प्रारम्भ होकर नवम्बर तक होता है। फल को निकालने के लिए पुष्पावली गुच्छ को काटकर समस्त पेनिकिल निकाल लिए जाते हैं। पेनिकल में से पके हुए फलों को निकाल कर इन्हें छायादार शुष्क स्थान में सुखाया जाता है।

उपज : पौधे लगाने के तीसरे वर्ष में फसल उत्पादन प्राप्त होने लगता है। इलायची की अच्छी व स्वस्थ किस्मों को लगाने से प्रति

नाली 4-10 किग्रा. (प्रति हेक्टेयर 400-1000 किग्रा.) का उत्पादन होता है। प्रति नाली ₹ 8000.00 से 20,000.00 की आय प्राप्त होती है, जो कि अगले वर्षों में बढ़ती जाती है।

फलों को सुखाने की विधि : प्राय: लोग बड़ी इलायची के फलों को पेनिकल में से तोड़ कर व धोने के बाद 60 से 72 घंटे (गहरे भूर रंग होने तक) धूप में सुखाते हैं। यह एक लम्बी विधि है एवं इससे रंग व खुशबू भी कम हो जाती है जिससे इन फलों का मूल्य भी अच्छा नहीं मिल पाता है।

वैज्ञानिक तरीका : फलों को पेनिकल से तोड़ने के उपरान्त पानी से धो देते हैं जिससे फलों में लगी मिट्टी साफ हो जाये। कमरे में कृत्रिम तापमान (40-50 डिग्री सेंटी.) तैयार कर फलों को जमीन से ऊपर तख्त/चारपाई में बांस (रिंगाल) या जूट से बनी चटाइयों पर सुखाने के लिए बिछा देते हैं। इस तापमान पर कम से 3-4 घंटे (जब तक उनका रंग गहरे भूरे रंग का न हो जाए) फलों को सुखाया जाता है। इस तकनीक से फल जल्दी सूख जाते हैं और उनका अच्छा रंग व खुशबु बनी रहती है। इस प्रकार के फलों का बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त होता है।

बड़े स्तर पर इलायची की खेती करने वाले किसान इलायची के फल को सुखाने के लिए बाजार में उपलब्ध विभिन्न के ड्रायर का प्रयोग भी कर सकते हैं।

विपणन : इलायची के विपणन में विभिन्न विभाग जैसे-जिला भेषज संघ, उद्यान विभाग आदि सहयोग करते हैं।

श्री संजय सक्सेना
कार्यक्रम प्रबंधक: कृषि/उद्यान
UGVS-ILSP

गतिविधि

फैडरेशनों/आजीविका संगठनों का बाजार लिंकेज

परियोजना द्वारा फैडरेशनों/आजीविका संगठनों को उत्पादों के विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराने एवं बाजार के अनुरूप उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकिंग आदि की जानकारी उपलब्ध कराने तथा बाजार की माँग को समझने के उद्देश्य से राज्य एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों/प्रदर्शनियों में फैडरेशनों/आजीविका संगठनों को प्रतिभाग कराया जाता है। इन मेलों/प्रदर्शनियों में फैडरेशनो/आजीविका संगठनों द्वारा अपने स्टॉल लगाकर उत्पादों की बिक्री की जाती है तथा अधिक मात्रा में उत्पादों की सप्लाई के ऑर्डर प्राप्त किये जाते हैं। माह सितम्बर 2015 से जनवरी 2016 तक 57 फैडरेशनों ने कुल 12 मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग कर कुल ₹ 13.05 लाख का विपणन किया तथा ₹ 12.70 लाख के आर्डर प्राप्त किये–

मेले/प्रदर्शनियाँ	मेलों का अनमानित बिजनेस	
	टर्नओवर (₹)	प्राप्त आर्डर (₹)
अतंर्राष्ट्रीय कृषि मशीनरी एक्सपो, करनाल, हरियाणा	65,000	1,50,000
उत्तराखण्ड ट्रेड फेयर, देहरादून	2,00,000	2,00,000
नेचर फैस्टीवल, देहरादून	35,000	50,000
उत्तराखण्ड सरस मेला, देहरादून	3,15,000	3,00,000
उत्तराखण्ड सृजन नेशनल एक्सपो एवं सेमीनार, देहरादून	30,000	20,000
अतंर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, दिल्ली	5,000	2,50,000
उत्तराखण्ड अतंर्राष्ट्रीय सहकारिता प्रर्दशनी, देहरादून	4,50,000	3,00,000
गोचर व्यापार मेला, चमोली	1,00,000	-
नैनबाग शरदोत्सव	20,000	-
क्रेता विक्रेता सम्मेलन, नई दिल्ली	-	4,00,000
आजीविका बाजार, अल्मोड़ा	25,000	-
माघ मेला, उत्तरकाशी	30,000	-
उत्तरायणी मेला, बागेश्वर	30,000	-

परियोजनान्तर्गत बाजार लिंकेज हेतु अभिनव प्रयास करते हुए फैडरेशनों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। इससे जहाँ एक ओर फैडरेशनों को स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हें स्थानीय उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। परियोजनान्तर्गत बाजार लिंकेज हेतु अभिनव प्रयास करते हुए फैडरेशनों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। इससे जहाँ एक ओर

फैडरेशनों को स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हें स्थानीय उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। वर्तमान में जनपद चमोली, अल्मोड़ा एवं रूद्रपयाग की चार फैडरेशनों के मध्य बाजार लिंकेज स्थापित हुआ है। इसके अन्तर्गत 45 कुं. मंडुवा तथा 150 कुं. आलू का बीज एक दूसरे को उपलब्ध कराते हुए इस नवीन पहल की शुरूआत की गई है।

परियोजना द्वारा फैडरेशनों/आजीविका संगठनों को राज्य से बाहर बाजार लिंकेज स्थापित कराते हुए स्थानीय कृषि उत्पादों के ऑर्डर फैडरेशनों को निम्नानुसार उपलब्ध कराये गये हैं–

- इमामी प्रा.लि. से 20 कुं. कुटकी ऑर्डर रूपकुण्ड स्वायत्त सहकारिता चमोली को।
- विनोधारा बायोटैक से 20 कुंतल मटर का ऑर्डर प्रगति, बिसजुला, चेतना, माँ पूर्णागिरी तथा नारी एकता स्वायत्त सहकारिता अल्मोड़ा को।
- सी.टी.डी. (फार्मर) से 150 कुं. नींबू का ऑर्डर रूपकुण्ड, स्वायत्त सहकारिता घाट चमोली को।
- पहाड़ी शॉप से 10 कुं. दालों का ऑर्डर चन्द्रबदनी टिहरी तथा हरिकुल स्वायत्त सहकारिता चमोली को।
- परियोजना की तकनीकी एजेंसी हार्क के सहयोग से जनपद देहरादून, कालसी विकासखण्ड के लखवाड़, बिहाल, बागी, जखनऊ बिस्तौं गाँव के 1-1 उत्पादक समूह तथा धनपौं गाँव के 2 उत्पादक समूहों द्वारा कुल 150 कुं. मक्का के बीज की आपूर्ति तराई विकास बीज निगम, हल्द्वानी को की गई।

श्री मनोज रावत
कार्यक्रम प्रबंधक: मार्केट एक्सेस
UGVS-ILSP

गतिविधि

साहस व हिम्मत की मिसाल बकरी पालन - रतमटिया गाँव

गरूड, बागेश्वर

ग्राम पंचायत रतमटिया सड़क मार्ग से दो किमी. की दूरी पर है। रतमटिया गाँव की सीमा जंगल से लगी हुयी है। यहाँ के अधिकतर परिवार बी.पी.एल. श्रेणी के हैं। ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन खेती व पशुपालन है। सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण खेती वर्षा पर आधारित है।

परियोजना की तकनीकी संस्था श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने गाँव में उत्पादक समूह गठन एवं आजीविकावर्द्धन करने हेतु गतिविधि चयन संबंधी चर्चा की। 24 परिवारों के तीन समूह- विजय, लक्ष्मी एवं दुर्गा उत्पादक समूह का गठन हुआ। खेतों में सिंचाई सुविधा न होने तथा खेतों में जंगली जानवरों के प्रकोप को देखते हुये ग्रामवासियों ने बकरी पालन को अपनी प्रथम आयअर्जन गतिविधि के रूप में चयनित किया। इस गतिविधि हेतु उत्साहित सभी 24 परिवारों को परियोजना द्वारा 3600 रूपये की प्रथम सहयोग धनराशि दी गयी। बकरी क्रय करने हुतु सभी सदस्यों द्वारा अंशदान के रूप में स्वयं की धनराशि का भी उपयोग किया। सभी 24 सदस्यों ने सामूहिक रूप से एक साथ बकरियों की खरीद की। इस दौरान परियोजना के मार्गदर्शन में बकरियों के नस्ल सुधार हेतु समूह की सदस्या श्रीमती हेमा देवी के नाम का प्रस्ताव पशुपालन विभाग को नर बकरा उपलब्ध कराने हेतु भी दिया गया है।

वर्तमान में तीनों समूहों के सदस्यों के पास 48 बकरियाँ हैं, जिनमें 13 सदस्यों की बकरियां निकट भविष्य में प्रजनन करने वाली हैं। जंगल में बकरी चराते हुए कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। दो माह पहले की घटना है, विजय उत्पादक समूह की अध्यक्ष श्रीमती शोभा देवी पर जंगल में बकरी चराते समय तेंन्दुए ने हमला किया। शोभा देवी के उल्टा वार करने व शोर मचाने पर तेन्दुआ भाग गया। इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज भी उत्साहपूर्वक बकरी पालन कर रही हैं।

विजय उत्पादक समूह की दूसरी सदस्य मीरा देवी, जो परिवार वालों के विरोध के बावजूद भी अपनी स्वेच्छा से समूह में जुड़ी। परियोजना द्वारा सहयोग राशि मिलने के उपरान्त उन्होंने एक बकरी खरीदी तो परिवार वालों ने भी परियोजना पर भरोसा किया व खुशी-खुशी मीरा देवी का सहयोग कर रहे हैं।

इसी समूह की सदस्य श्रीमती मानुली देवी जो कि अनुसूचित जाति की महिला हैं। इनकी बकरी बीमारी के कारण मर गई, तो इन्होंने उसके बाद पुन: एक बकरी खरीदी। कुछ समय बाद बकरी पालन का विस्तार करते हुए दो और बकरियाँ और खरीदी।

तीनों समूह सदस्य बारी-बारी जंगल में बकरी चराने का कार्य कर रहे हैं। आने वाले दो तीन महीनों के बाद बकरी बेचने योग्य होने वाली हैं, बकरी बेचने के लिए गाँव के आस पास पर्याप्त मात्रा में बाजार व्यवस्था है।

प्रभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई
जनपद बागेश्वर,UGVS-ILSP

शोक समाचार

बड़े दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्री प्रदीप सिंह नेगी सहायक प्रबन्धक- PM&E, KM, UGVS बागेश्वर अब वह हमारे बीच नहीं रहे। दिनाँक 25 दिसम्बर 2015 को उनका हृदयगति रूकने के कारण, उनके गृह जनपद रूद्रप्रयाग में निधन हो गया है। एकीकृत आजीविका परिवार को उनकी कमी हमेशा खलेगी। भगवान उनके परिवार को इस गहरे दु:ख एवं क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें।

एकीकृत आजीविका परिवार

– सम्पर्क पते –

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS)

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई

- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, अल्मोड़ा
  टेलीफैक्स: 05962-230910, 230305,
  ईमेल: dpmalmora@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, बागेश्वर
  टेलीफैक्स: 05963-221502, 211746
  ईमेल: dpmbageshwar@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, चमोली
  टेलीफैक्स: 01372-251355, 251451
  ईमेल: dpmchamoli@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, टिहरी
  टेलीफैक्स: 01376-256133, 256249
  ईमेल: dpmtehri@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तरकाशी
  टेलीफैक्स: 01373-223925, 223466
  ईमेल: dpmuttarkashi@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, रुद्रप्रयाग
  ईमेल: dpmrudraprayag@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, पिथौरागढ़
  ईमेल: dpmpithoragarh@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, देहरादून
  ईमेल: dpmdehradun@ugvs.org

परियोजना की सहयोगी संस्थाएं

क्र०सं०	तकनीकी एजेंसियां	ब्लॉक समन्वयक	विकासखण्ड	जनपद
1	CBED (सीबैड), (सेंटर फॉर बिजनेस एण्ड एंटरप्रिनोरियल डवलेपमेंट सोसायटी, देहरादून	9410131570 9012665853	जौनपुर मुनाकोट	टिहरी पिथौरागढ़
2	SBMA (एस०बी०एम०ए०) (श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, टिहरी)	9927465474 8937090529	गरूड घराली	बागेश्वर चमोली
3	GRASS(ग्रास) (ग्रामीण समाज कल्याण समिति, अल्मोड़ा)	9412167235 9412927804	हवालबाग सल्ट	अल्मोड़ा
4	ATI (ए०टी०आई०) (एप्रोपिएट टैक्नोलोजी इंडिया, देहरादून)	8006407512 8006407505	भटवाड़ी चम्बा	उत्तरकाशी टिहरी
5	ASEED (असीड), (एशियन सोसायटी फॉर एंटरप्रिन्योरशिप एजुकेशन एड डवलेपमेंट, दिल्ली)	8476899997 9756829729	जखोली अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग
6	IFFDC (आई०एफ०एफ०डी०सी०), (इण्डियन फार्म फॉरेस्ट्री डवलपमेंट को-ऑपरेटिव लि०, गुड़गाँव)	9456595651 9456595651	भिकियासैण चौखुटिया	अल्मोड़ा
7	HARC (हार्क) हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून)	9456166215 9971499218	कालसी चकराता	देहरादून
8	SWATI (स्वाति), (स्वाति ग्रामोद्योग संस्थान, धारचुला पिथौरागढ़)	9927021731	बिण	पिथौरागढ़
9	वरदान, देहरादून	9412059310	कल्जीखाल	पौड़ी
10	RADS (राडस) (रूरल एरिया डवलेपमेंट समिति, रानीचौरी, टिहरी)	9412927804	स्यालदेह	अल्मोड़ा

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना कार्यक्षेत्र

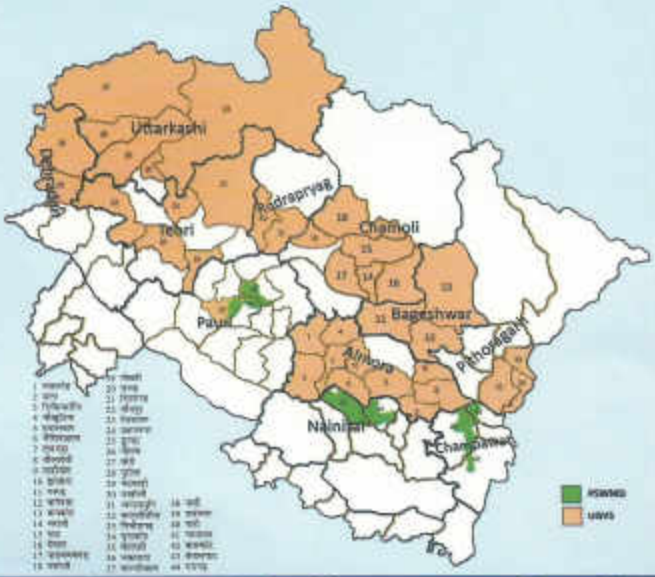

परियोजना समिति–जलागम प्रबंध निदेशालय (PS-WMD)

परियोजना समिति–जलागम प्रबंध निदेशालय,
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना
इन्दिरानगर, देहरादून, टेलीफैक्स: 0135-2760362,
ईमेल: pdilsp.wmd@gmail.com

प्रभाग कार्यालय

- प्रभाग कार्यालय ILSP-WMD, पौड़ी
  मो० : 9411113132 ईमेल: dpdilsppauri@gmail.com
- प्रभाग कार्यालय ILSP-WMD, नैनीताल
  मो० : 9456540839, ईमेल: dpdhaldwani@rediffmail.com
- प्रभाग कार्यालय ILSP-WMD, चम्पावत
  मो० : 9411113414, ईमेल: dpdchampawat@gmail.com

परियोजना फील्ड एन.जी.ओ.–HIFEED

(Himalayan Institute For Environment Ecology & Development)

- एन.जी.ओ.समन्वयक, ILSP-WMD, पौड़ी, मो० : 9756155431
- एन.जी.ओ.समन्वयक, ILSP-WMD, नैनीताल, मो० : 7838823689
- एन.जी.ओ.समन्वयक, ILSP-WMD, चम्पावत, मो० : 9410901693

प्रकाशक: श्री विजय कुमार, परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति
संपादकीय टीम: ज्ञान प्रबंधन इकाई
पता: 216, फेज II, पंडितवाड़ी, देहरादून, टेलीफैक्स: 0135-2774800, 2773800
ईमेल: info@ugvs.org,km@ugvs.org वेबसाइट: www.ugvs.org

IFAD
Investing in rural people

केवल सीमित वितरण हेतु प्रकाशित